अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ● आगरा
नई दिल्ली ■ बुधवार, 3 सितंबर 2025

आरएसएस के लक्ष्य व्यापक और दूरगामी हैं, जबकि सरकारें तो अस्थायी होती हैं। -वाल्टर के एंडरसन

सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश चेताती है कि हमें प्रकृति के संकेतों को गंभीरता से लेना होगा और यह भी कि जलवायु परिवर्तन व मानवीय लापरवाही का संयुक्त असर कितना घातक हो सकता है। एकजुट और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनकर ही हम प्रकृति के प्रकोप से उबर सकते हैं।

प्रकृति के संकेत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान समूचे उत्तर भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं, जहां पहले ही मानसून ने भारी तबाही मचाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर, 2025 में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की आशंका है, जो दीर्घकालिक औसत से 109 फीसदी अधिक हो सकती है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए तो, जो पहले ही बाढ़ और भू-स्खलन की आपदाओं से जूझ रहे हैं, यह और भी गंभीर चेतावनी है। समूचा हिमाचल प्रदेश पहले ही आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, स्थितियां राजधानी में भी अच्छी नहीं हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और अधिकारीगण डूब क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं। गुरुग्राम में 20 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जलभराव के दृश्य देखकर ही पता चलता है कि आम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में अगस्त में 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश होना चिंताजनक है, लेकिन अधिक परेशान करने वाला तो यह पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। कुल मिलाकर, यह जरूरी हो गया है कि हम इस आसन्न संकट के प्रति सजग हों और इसके प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। संकट इस बात का है कि इस भारी बारिश का असर केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। शहरी केंद्रों जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ इत्यादि में जलभराव और यातायात की समस्याएं, तो उत्तराखंड में तीर्थयात्राएं प्रभावित होने से, पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचा है। अतिशय बारिश किसानों की फसलों को नष्ट कर रही है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई की आशंका बढ़ रही है। भू-स्खलन के चलते कइयों ने जान गंवाई है, तो कई अब भी लापता हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को

सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई करने की सलाह दी है। फिलहाल संकट से निपटने के लिए जिन तात्कालिक उपायों की जरूरत है, उन पर तो सरकारें ध्यान देंगी ही, हैरत की बात तो अलबत्ता यह है कि हर साल बारिश के मौसम में ऐसी ही स्थितियां खड़ी होने पर भी हम खुद को वहीं के वहीं खड़ा पाते हैं। दरअसल, स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर लक्षित ठोस नीतियों की दरकार है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और टिकाऊ जीवनशैली को अपनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए बगैर हम ऐसी आपदाओं को बार-बार झेलने के लिए मजबूर होंगे।

सौ साल और संघ की छवि

जब संघ बीते कई दशकों से भारतीय समाज के हर आयाम में सक्रिय है-चाहे राजनीतिक हो या श्रमिक, कृषि हो या शिक्षा, प्रशासन हो या संस्कृति-तब उसे अपने 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी अपने विचारों-उद्देश्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

गत दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। देश-विदेश से आए सैकड़ों गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सरसंघचालक मोहन भागवत ने पहले दो दिनों में संघ की भूमिका, इतिहास और उद्देश्य पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। तीसरे दिन लगभग ढाई घंटे तक चले प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने 200 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष प्रश्न है-जब संघ बीते कई दशकों से भारतीय समाज के हर आयाम में सक्रिय है-चाहे राजनीतिक हो या श्रमिक, कृषि हो या शिक्षा, प्रशासन हो या संस्कृति-तब उसे अपने 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी अपने विचारों-उद्देश्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

बलबीर पुंज
पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

वास्तव में, जो संघ अब तक कहता-करता रहा है और जो देश-विदेश में उसकी छवि है, उसमें भारी अंतर है। संक्षेप में कहें, तो संघ आज भी 'छवि-अभाव' और 'नकारात्मक धारणा' का शिकार है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला-संघ अद्वितीय संगठन है, जिसका समकक्ष पश्चिमी सभ्यता में कहीं नहीं मिलता। भारतीय समाज का एक वर्ग, जो आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है, वह अपने अंतर्निहित पश्चिमी दृष्टिकोण से संघ को समझने की कोशिश करता है, इसलिए वास्तविकता को समझने में गलत साबित होता है। मोहन भागवत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि संघ को बाहर से समझना कठिन है और उसकी कार्यपद्धति को भीतर जाकर ही समझा जा सकता है।

वास्तव में, संघ इस तरह की गलतफहमी का शिकार पहला नहीं है। गांधी जी की विचार-प्रणाली, कार्यपद्धति, जीवनशैली और नीतियां भी पश्चिमी सभ्यता की परंपरागत बौद्धिक समझ से परे थीं। इस पर ब्रितानी पत्रकार किंग्सले मार्टिन (1897-1969) ने अपने लेख 'महात्मा गांधीः संत या राजनीतिज्ञ' में लिखा थाः 'जब 1931 में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में पहली बार देखा, तो मैंने स्वयं से पूछा कि वे कितने संत हैं

और कितने राजनीतिज्ञ। बाद में, मुझे अनुभव हुआ कि यह प्रश्न ही निरर्थक है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ये दोनों ही जटिल रूप से समाहित थे।' मार्टिन का यह अवलोकन संघ पर भी लागू होता है। स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका और उसकी संभावनाओं को ब्रितानी भली-भांति समझ चुके थे, इसलिए 1925 में स्थापना के पांच वर्षों के भीतर ही संघ को 1930-32 के बीच ब्रितानी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

दूसरा-संघ पर उसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और उनके चिंतन की गहरी छाप विद्यमान है। संयोगवश डॉ. हेडगेवार और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू-दोनों का जन्म 1889 में ब्राह्मण परिवारों में हुआ था, किंतु यह समानता यहीं समाप्त हो जाती है। नेहरू जी का पालन-पोषण तत्कालीन भारत के सर्वाधिक कुलीन, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली परिवेश में हुआ, जहां उनका लालन-पालन यूरोपीय जीवनदर्शन-संस्कारों के अनुरूप हुआ। वर्ष 1905-12 तक इंग्लैंड में अध्ययन करने बाद भारत लौटे नेहरू जी कांग्रेस से जुड़े और 31 वर्ष की आयु में औपचारिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रविष्ट हुए। डॉ. हेडगेवार एक साधारण विद्यार्थी के रूप में ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ चुके थे। वर्ष 1897 में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की 60वीं वर्षगांठ पर उनके विद्यालय में मिठाई वितरित की गई थी। तब आठ वर्षीय केशव ने उसे ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। देश को स्वाधीन कराने की यही तीव्र इच्छा उन्हें तत्कालीन कलकत्ता के प्रसिद्ध क्रांतिकारी समूह 'अनुशीलन समिति' में ले आई। आगे चलकर वह कांग्रेस में भी शामिल हुए और उसके समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया। कालांतर में डॉ. हेडगेवार कांग्रेस की विदर्भ इकाई के संयुक्त सचिव भी बने। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण उन्हें अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में 1921 में एक वर्ष के कठोर कारावास में भेज दिया। खिलाफत आंदोलन (1919-24) के बाद उन्हें आभास हुआ कि देश की समस्याएं दीर्घकालिक हैं, जिनका राजनीतिक दल या सत्ता के माध्यम से समाधान संभव नहीं। तब उन्होंने 36 वर्ष की आयु में आरएसएस का गठन किया।

डॉ. हेडगेवार के स्वभाव पर संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने नाना पालकर की पुस्तक 'मैन ऑफ द मिलेनिया-डॉ. हेडगेवार' की प्रस्तावना में लिखा था, '...सबसे बड़ी बाधा चरित्र प्रचार से विरक्ति थी। डॉक्टर जी ने स्वयं अपने जीवन के किसी भी पक्ष को सार्वजनिक रूप से प्रायः साझा नहीं किया। इसी स्वभाव के कारण उनका उल्लेख समाचारपत्रों में भी बहुत कम दिखाई देता है...अपनी अंतिम श्वास तक कार्य में निरंतर तत्पर और पूर्णतया तल्लीन रहने वाले डॉक्टर जी के मनोभाव में आत्मकथा लिखने या उसके लिए कोई नोट्स संकलित करने का विचार कभी अंकुरित ही नहीं हुआ।' आज भी संघ की कार्यपद्धति पर डॉ. हेडगेवार के व्यक्तित्व की छाया है।

तीसरा-संघ का विरोध प्रायः उन वर्गों द्वारा किया जाता है, जो भारत को जीवंत सनातन राष्ट्र न मानकर मात्र भूमि का एक टुकड़ा समझते हैं और भाषाई-मजहबी आधार पर इसके विभाजन को उपयुक्त कहते हैं। पाकिस्तान इसी विषैली मानसिकता की उपज है। संघ का प्रकट ध्येय मजहब-संप्रदाय और जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय समाज को समरसता के साथ एकसूत्र में पिरोना, उसे आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और राष्ट्रनिष्ठा से अभिसिंचित करना है। इसकी तुलना में कुछ अन्य पक्ष, समाज के असंतुष्ट वर्गों को अपने मिथ्यापूर्ण नैरेटिव से शासन-व्यवस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ खड़ा करने के लिए उकसाते हैं।

कहा जाता है कि आरएसएस ने अपनी नीतियों-कार्यों के प्रचार-प्रसार पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए उस रिक्तता को संघ-विरोधी अपने कुप्रचार से भर देते हैं। यही संघ की वास्तविकता और 'छवि' में अंतर का एक बड़ा कारण है। बेहतर हो कि शताब्दी वर्ष में संघ इस चुनौती का निर्णायक समाधान करे।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एलन वाट्स

जीवन का सार और वास्तविकता का अनुभव करने का एकमात्र अवसर वर्तमान क्षण में ही प्रकट होता है। भविष्य की योजना या अतीत के बारे में विचार तभी सार्थक होते हैं, जब वे मौजूदा वास्तविकता पर आधारित हों।

वर्तमान ही जीवन का असली रहस्य है

जीवन का अर्थ बस जीवित रहना है। यह एकदम स्पष्ट, प्रकट और साधारण है। इसके बावजूद हर कोई इतनी घबराहट में रहता है और इधर-उधर भागता फिरता है, मानो उसे खुद से बढ़कर कुछ हासिल करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा तब होता है, जब हम किसी आदर्श के अनुरूप जितना ज्यादा जीने की कोशिश करते हैं और उतना ही महसूस होता है कि हम विफल हो रहे हैं। हम इस दुनिया में आते नहीं हैं, बल्कि पेड़ के पत्तों की भांति हम उसमें से बाहर निकलते या प्रकट होते हैं। जीवन का असली रहस्य तो यह है कि आप वर्तमान में जो भी कर रहे हैं, उसके साथ यहीं और अभी पूरी तरह जुड़े रहें। वर्तमान को काम के बजाय खेल की तरह महसूस करें।

जीवन को जीने की असली कला यह है कि लापरवाही की वजह से वर्तमान से भटकें नहीं और अतीत से डरकर चिपके भी न रहें। यह हर पल के प्रति संवेदनशील होने, उसे बिल्कुल नया और अनोखा मानने, और मन को खुला और पूरी तरह ग्रहणशील रखने में निहित है। जीवन अपने आप में एक संगीत है। हम शाश्वत वर्तमान में जी रहे हैं, और जब हम संगीत सुनते हैं, तो हम अतीत को नहीं सुन रहे होते, हम भविष्य को नहीं सुन रहे होते, हम एक विस्तृत वर्तमान को सुन रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप हर रात कोई भी सपना देख सकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। और उदाहरण के लिए, आपके पास एक रात में 75 साल या जितना चाहें उतना लंबा सपना देखने की शक्ति हो। और स्वाभाविक रूप से, जैसे ही आप सपनों के इस रोमांच की शुरुआत करेंगे, आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आपको हर तरह का सुख मिलेगा, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और 75 साल के पूर्ण सुख की कई रातों के बाद, आप कहेंगे, 'वाह, यह तो बहुत अच्छा था।' लेकिन अब एक आश्चर्य होता है।

मान लीजिए एक ऐसा सपना आता है, जो नियंत्रण में नहीं है। जहां मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वह क्या होगा और आप उसे गहराई से समझेंगे तथा उससे बाहर आकर कहेंगे, 'वाह, यह तो बाल-बाल बच गया, है न?' और फिर आप और भी साहसी होते जाएंगे, और आप इस बारे में और भी जोखिम भरे दांव लगाएंगे कि आप क्या सपना देखेंगे। अंततः आप वह सपना देखेंगे, जहां आप अभी हैं। आप उस जीवन को जीने का सपना देखेंगे, जो आप वास्तव में आज जी रहे हैं।' जीवन का सार और वास्तविकता का अनुभव करने का हमारा एकमात्र अवसर वर्तमान क्षण में ही प्रकट होता है। भविष्य की कोई भी योजना या अतीत के बारे में विचार तभी सार्थक होते हैं, जब वे वर्तमान वास्तविकता पर आधारित हों। मन अक्सर अतीत को दोहराकर या भविष्य की कल्पना करके भटकाव पैदा करता है, लेकिन इससे जीवन में देरी होती है और एक लुप्त समय को बल मिलता है।

सही जगह लगाएं ध्यान

सूत्र

भागदौड़ भरे जीवन में, हम अक्सर तनाव और अशांति महसूस करते हैं। हमारा मन भटकता फिरता है, कभी भविष्य की ओर, तो कभी अतीत में डूबा रहता है। हमें लगता है कि मन की शांति केवल पहाड़ों की चोटी पर ही संभव है, लेकिन वह शांति हम अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ध्यान को सही जगह लगाएं, हमेशा वर्तमान में रहें।

दूसरा पहलू

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल रोजा-ए-मुन्नवरा यानी ताजमहल इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है।

ताजमहल, लकड़ी की बुनियाद और यमुना की खिसकती धारा

क्या किसी नदी किनारे रेत पर मजबूत इमारत तामीर हो सकती है। इसका जवाब है ताजमहल। गाइड तो यह भी अफसाना कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनाने वालों के हाथ काट दिए, जिससे वे दोबारा ऐसी इमारत न बना सकें। खैर, यह सब तो पर्यटकों को लुभाने के लिए गढ़े गए किस्से हैं, पर ताजमहल यमुना के रेत पर कैसे बना इसे जानने के लिए उस समय की वास्तुकला, वास्तुशिल्प, अभियांत्रिकी की अनोखी दास्तान के जर्द हो चुके पन्नों को पलटना होगा।

भूपेंद्र कुमार

शाहजहां की आत्मकथा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार, बालू वाली जमीन पर मजबूत इमारत बनाना मुश्किल था।

यमुना किनारे की उस जगह को तब तक खोदा गया जब तक चट्टान के रूप में मजबूत आधार नहीं मिल गया। इनमें साल की लकड़ी के बने लट्ठे डाले गए और बाकी जगह को पत्थरों से भरा गया।

शाहजहां की बेगम अर्जुमंद बानो यानी मुमताज नूरजहां की भतीजी थीं। 27 अप्रैल, 1593 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था। वयस्क होने पर शहजादे खुर्रम (शाहजहां) से उनका निकाह हो गया। मुमताज और शाहजहां में बेपनाह मोहब्बत थी। वह युद्ध अभियानों में भी साथ रहती थीं। दक्कन अभियान के दौरान 17 जून, 1631 को बुरहानपुर में 14वें शिशु को जन्म देने के कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। शाहजहां का इरादा पहले बुरहानपुर में स्मारक बनाने का था, पर उसे आगरा भी लौटना था। 12 दिसंबर, 1631 को मुमताज का पार्थिव शरीर शहजादा शुजा आगरा लेकर आया। अब शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का इरादा किया जैसा कहीं न हो। शाहजहां का सपना 1653 ईस्वी में पूरा हुआ।

ताजमहल को रोजा ए मुन्नवरा भी कहा जाता है यानी जगमगाता मकबरा। इसकी रूपरेखा तुर्की निवासी ईसा अफंदी द्वारा बनाई गई। सबसे बड़ी चुनौती शाहजहां द्वारा पसंद की गई यमुना किनारे की बलुई भूमि थी। शाहजहां की आत्मकथा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार, पानी के किनारे बालू वाली जमीन पर मजबूत इमारत बनाना बेहद मुश्किल था। इसके लिए शाहजहां के वास्तुकारों ने जो योजना बनाई वह कमाल की थी। इसके लिए यमुना किनारे की उस जगह को तब तक खोदा गया जब तक चट्टान के रूप में मजबूत आधार नहीं मिल गया। 25 हजार टन वजनी ताजमहल और प्लेटफॉर्म को मजबूत नींव की दरकार थी, 12 हजार टन तो अकेले गुंबद का वजन था। इसके लिए 50 कुएं खोदे गए। इनमें साल की लकड़ी के बने लट्ठे डाले गए और बाकी जगह को पत्थरों से भरा गया। कुओं को इस तरह बनाया गया कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रही। अंदर की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वह उतनी मजबूत होगी। यह उस वक्त की बात है, जब यमुना ताजमहल से सटकर बहती थी, बहरहाल अब धारा खिसक गई है। यमुना में पानी भी बस मानसून के दौरान रहता है। इससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल की नींव को लेकर चिंता भी पैदा हो गई है।

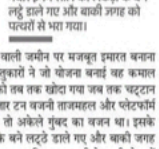

आंकड़े

भारतवंशी नेता

दुनिया के 29 देशों में भारतीय मूल के 261 नेता वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनमें से कई तो राष्ट्र प्रमुख तक बने हैं।

मॉरीशस	45
गुयाना	33
ब्रिटेन	31
फ्रांस	24
सूरीनाम	21

आंकड़े संबंधित देशों में प्रमुख भारतवंशी राजनेताओं के | स्रोत : MEA

मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन माता यशोदा ने अपने लल्ला को नगर भ्रमण कर जल स्नान कराया था। तब से यह परंपरा अब तक चली आ रही है।

ठाकुर जी का जल विहार

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि राजा बलि के द्वारपाल बने भगवान श्रीहरि विष्णु इस दिन करवट लेते हैं और वामन अवतार की पूजा होती है। लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इस एकादशी को भगवान के जल विहार करने को उत्सव के रूप में मनाते हैं।

कथा है कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपने लल्ला को नगर भ्रमण करवाकर जल स्नान करवाया था। इसके बाद से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। पालकी, डोली या डोला, जिसमें ठाकुर जी यानी भगवान को विराजित करते हैं। इसके बाद संबंधित ग्राम-नगर में बड़े ही भक्ति भाव के साथ पालकी में बिठाकर ठाकुर जी को यात्रा करवाते हैं, फिर तालाब के पवित्र जल में ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है और बाद में फिर मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है।

अंतर्यात्रा
संकलित

इसे ठाकुर जी की जल विहार कहते हैं। इस दिन कई जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। एक मान्यता है कि राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ गया। तीन वर्ष तक बारिश नहीं हुई। जब उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, तब जाकर बारिश हुई। इस एकादशी का व्रत करने से भक्ति भाव बढ़ता है और भगवान अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से —— 03 सितंबर, 1953

अमेरिका की चीन को धमकी हिंदचीन में हस्तक्षेप सहन नहीं

अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने भूतपूर्व अमेरिकी सैनिकों के बीच कहा, 'यदि चीन ने हिंदचीन में कोई भी संगीन कार्रवाई की, तो ऐसी स्थिति में हम जो कदम उठाएंगे, वह उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा।'

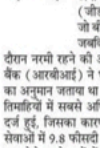

विकास की रफ्तार बनी रहेगी

पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की दर से जीडीपी में वृद्धि दर्शाती है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

सतीश सिंह

आर्थिकी

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आई तेजी से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अनापेक्षित रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जो बीती पांच तिमाहियों में सर्वाधिक है, जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इस दौरान नरमी रहने की आशंका जताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी वृद्धि दर के 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। जून तिमाही में सेवा क्षेत्र में आठ तिमाहियों में सबसे अधिक 9.3 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज हुई, जिसका कारण लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 9.8 फीसदी की दर से व वित्तीय, रियल एस्टेट तथा पेशेवर सेवाओं में 9.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज होना है। विनिर्माण क्षेत्र में पिछली चार तिमाहियों में सबसे अधिक 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

श्रम बहुल निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर विगत नौ तिमाहियों में सबसे कम 7.6 प्रतिशत रही। वहीं, इस तिमाही में कृषि उत्पादन में 3.7 फीसदी की दर से वृद्धि

ज्यादा है। जून तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 8.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जबकि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए 10.1 फीसदी वृद्धि दर का अनुमान जताया था। ज्ञात हो कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर की गति धीमी रहने से सरकार के लिए राजकोषीय घाटे और कर्ज-जीडीपी अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुश्किलें हो सकती हैं, पर उम्मीद है कि आगामी तिमाही में इसमें अपेक्षित तेजी आएगी।

गौरतलब है कि आलोच्य अवधि में ऋण वितरण में

और भी बेहतर होती। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 27 जून, 2025 तक बैंक ऋण वृद्धि दर सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 184.83 लाख करोड़ रुपये हो गई। 28 जून, 2024 तक यह ऋण 168.86 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी खर्च की दर बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की तुलना में सात फीसदी बढ़ी, जो बेहतर मांग को दर्शाती है, जबकि सरकारी खर्च 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

इसी तरह, आयकर में राहत, रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती, खरीफ बुआई की बेहतर स्थिति और वस्तु एवं सेवा कर में सुधार आदि से निजी खपत में तेजी आई है। एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर छह प्रतिशत हो गई, जो विगत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में पांच प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में निजी अंतिम उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 60.3 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 58.3 प्रतिशत रही थी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जीएफसीएफ में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि, यह पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की तुलना में दर्ज 9.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कम रही। जीएफसीएफ को अर्थव्यवस्था में परोक्ष रूप से निवेश मांग के संकेत रूप में देखा जाता है। बहरहाल, आगामी तिमाहियों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से

जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से केंद्र सरकार का सकल राजस्व बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल जुलाई में संग्रह से 7.5 फीसदी अधिक व जून 2025 में संग्रह से छह फीसदी ज्यादा है। जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि दर्शाती है कि देश में आर्थिक गतिविधियां जारी हैं। यह भी माना जा रहा है कि जीएसटी की नई दरों के प्रभाव में आने के बाद देश में उपभोग मांग में बढ़ोतरी हो सकती है।

अमेरिका द्वारा लगाए गए हालिया टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रतिकूल प्रभाव चालू वित्त वर्ष में घरेलू निजी निवेश पर आंशिक असर पड़ सकता है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश के कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत योगदान इस क्षेत्र का है। अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान की भी यात्रा की और जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, दूसरे देशों के साथ कारोबारी करार करने की दिशा में भी भारत काम कर रहा है।

विश्लेषण से साफ है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर आंशिक असर पड़ेगा। देश में निवेश, मांग और खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में काफी बढ़िया रहा है। इस साल मानसून भी ठीक रहा है। खरीफ की बुआई बेहतर रही है। ऋण वितरण में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई नियंत्रण में है। ऐसे में सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी का दौर आगामी तिमाहियों में भी जारी रह सकता है और चालू वित्त वर्ष में

हिन्दुस्तान 1936

बाढ़ और भूकंप

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक अतिवर्षा, बाढ़ और जलभराव के जो मंजर हमारे सामने हैं, वे कुदरत की अकल्पनीय विध्वंसक क्षमता का तो एहसास करा ही रहे हैं, इंसानी हिमाकतों की कलई भी खोल रहे हैं। खासकर गुरुग्राम की पॉश कॉलोनियों में सोमवार की बारिश के बाद जलभराव और दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग पर वाहनों के जाम के दृश्यों ने एक बार फिर एहसास कराया कि शहरी ढांचों के विकास और प्रबंधन के लिहाज से अभी कितनी सारी कमियां हमें दूर करनी हैं। शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञ दशकों से आगाह करते आ रहे हैं कि डूब क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जल-निकासी के स्वाभाविक रास्तों के अतिक्रमण को लेकर भी उनकी चेतावनियां अनसुनी की जाती रही हैं। ऐसे में, साल-दर-साल ऐसी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसके लिए सिर्फ सरकारी तंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। सुविधाओं की मांग सहयोग का कर्तव्य निभाए बिना कभी सफल नहीं हो सकती। दुर्योग से, जाम जैसी मानव-कृत समस्याएं बताती हैं कि यह सोच हमारी नागरिक-संस्कृति का अब तक हिस्सा नहीं बन पाई है।

विडंबना यह है कि कुदरती आपदा के समय मानवीयता भी अपने श्रेष्ठतम रूप में हमारे सामने आती है। हिमाचल व जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से हुई हानि का आकलन अभी हो पाता, इसके पहले ही पंजाब में करीब एक दर्जन जिलों के लोगों की जिंदगी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गई है। सतलुज, ब्यास और रावी की उमड़ती धाराओं ने सूबे के करीब डेढ़ हजार गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। पशुपालकों के मवेशी बह गए हैं। गरीबों के जीवन पर इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ना स्वाभाविक है। मगर इस विपत्ति के समय जिस तरह पंजाब के दिलजीत दोसांझ, एमी वर्क, सोनू सूद जैसे बड़े कलाकारों ने अनेक गांवों व परिवारों को गोद लेने और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद करने का एलान किया है, वह वाकई प्रेरणादायी है। वहां के प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टरों में खाने-पीने के सामान, कपड़े, दवाएं व अन्य राहत सामग्रियां लेकर आम लोग पहुंच रहे हैं। यह पंजाबीयत की अनूठी मिसाल है।

पॉश कॉलोनियों में जलभराव और वाहनों के जाम के दृश्यों ने फिर एहसास कराया कि शहरी ढांचों के विकास व प्रबंधन की कितनी कमियों को दूर करने की जरूरत है।

ऐसा नहीं कि कुदरती कहर सिर्फ हिन्दुस्तान की सरहदों तक महदूद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी समान रूप से प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 20 लाख से अधिक लोगों को भयावह बाढ़ के कारण दरबदर होना पड़ा है। अब तक 850 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। उधर रविवार की देर रात अफगानिस्तान के जलालाबाद के करीब आए भूकंप ने वहां 1,400 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। साफ है, प्रकृति बार-बार संकेत दे रही है कि इंसानी समाज उसके निजाम को चुनौती देने की हिमाकत न करे। विज्ञान की बदौलत प्रकृति की चंद गतिविधियों का अंदाजा लगाकर इंसानी दुनिया जब इतराती है, तब अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखियों के विस्फोट, जंगलों की आग के जरिये वह विज्ञान की सीमाओं का भी एहसास कराती है। इसलिए विकास की मीनारें गढ़ते समय इन ज्ञात स्थितियों के गंभीर आकलन की जरूरत है। खासकर तब, जब हम स्मार्ट सिटी के विकास का खाका खींच रहे हैं, नए शहर बसाने के सपने संजो रहे हैं। विकास तो जरूरी है, पर विवेक गंवाकर नहीं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 03 सितम्बर, 1950

टंडनजी का अभिनन्दन

कांग्रेस-अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। सर्वश्री पुरुषोत्तमदास टंडन, आचार्य कृपलानी और शंकरराव देव की प्रतिद्वन्द्विता में बाजी टंडन जी के हाथ रही और बहुमत से वह निर्वाचित घोषित कर दिये गये। यों तो तीनों ही राष्ट्र के परखे हुए और मान्य व्यक्ति हैं, अतः किसी का भी अध्यक्ष चुना जाना अयुक्त न होता। फिर भी टंडन जी के चुने जाने पर हमें विशेष हर्ष है, क्योंकि कांग्रेसनिष्ठा के साथ-साथ उनकी राष्ट्रभाषानिष्ठा भी सोने में सुगंध का काम करती है। कांग्रेसी के रूप में कांग्रेस के मान्य सिद्धांतों पर तो टंडन जी की आस्था है ही, अतः उनके हाथों में कांग्रेस का गौरव सुरक्षित है। उनके अध्यक्ष हो जाने से राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसका उपयुक्त स्थान अपेक्षाकृत शीघ्र मिलने में सुविधा होगी, यह आशा करने का लोभ कोई भी हिन्दी प्रेमी संवरण नहीं कर सकता। उनके विचारों को जानते हुए राष्ट्र ने जब बहुमत से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, तो मानना चाहिए कि राष्ट्र की भी यही इच्छा है और उसके आगे सिर झुकाना सभी राष्ट्रभक्तों का कर्तव्य है।

टंडन जी के व्यक्तित्व का जहां तक संबंध है, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि वह सुवर्ण की तरह खरा है। चारित्र्य और साधुता में वह बेजोड़ हैं। सादगी और निर्मलता की वह मूर्ति हैं। भारतीयता उनका बाह्य गुण ही नहीं है, भोजन और चिकित्सा तक में वह उसको अमली रूप देते हैं। विचारों की स्थिरता और दृढ़ता उनके ऐसे गुण हैं, जिनके कारण उनके मित्र और उनके प्रति श्रद्धा या स्नेह रखनेवाले भी उन्हें पिघला नहीं पाते। सभाध्यक्ष के रूप में वह हर पक्ष का आदर प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह अपने पद का निर्वाह पूर्ण पक्षपातहीनता से करते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से पार्टीबाज उनके प्रति आदर रखते हुए भी हर बात में अपना साथ पाने के लिए उन पर निर्भर नहीं कर सकते। लेकिन यही सब बातें टंडन जी को साधारण जनों से उच्च कोटि का साबित करती हैं, जैसे कि वस्तुतः वह हैं भी। राजर्षि का सम्मान जो उन्हें दिया गया है वह अयुक्त नहीं है, यह स्पष्ट है। आज जब अनैतिकता और भ्रष्टाचार का प्राबल्य है, टंडन जी जैसे व्यक्तित्व का कांग्रेस-अध्यक्ष होना हमारे लिए संबल की तरह है। उनके नेतृत्व में देश इन बुराइयों को दूर करने का सक्रिय कदम उठायेगा, ऐसी आशा करनी चाहिए।

काम से बाहर गए लोगों को भूल न जाएं

राजीव शुक्ला | पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य

प्रवासियों की पीड़ा को समझना होगा। यह मान लेना कि जो मजदूर साल दो साल बाहर रह गया, उसका बिहार से कोई लेना-देना नहीं, न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

बिहार की पहचान सिर्फ उसकी मिट्टी और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों मजदूरों से भी जुड़ी है, जो रोज अपनी मेहनत से दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को जीवंत रखते हैं। देश के किसी भी बड़े शहर की चकाचौंध को आप यदि गौर से देखें, तो उनकी सड़कों, पुलों, इमारतों व फैक्टरियों से बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का पसीना टपकता हुआ नजर आएगा।

विडंबना यह है कि जब महामारी का संकट आया, तब यही मजदूर अचानक गैर-जरूरी समझ लिए गए। 2020 के लॉकडाउन की त्रासदी को कोई कैसे भूल सकता है? देश ने वह दर्दनाक मंजर देखा, जब मजदूर अपने परिवार, छोटे बच्चों और बूढ़े मां-बाप को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। रास्ते में भूख, प्यास और थकान से लोग टूटते गए। कइयों ने तो सड़कों पर ही दम तोड़ दिया।

इस भयावह त्रासदी के बाद सवाल उठे कि क्या अब बिहार अपने लोगों को रोजगार का विकल्प घर पर दे पाएगा? राज्य सरकार ने कुछ प्रयास किए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, बिहार कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी घोषणाएं की गईं। पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन शिविर लगाए गए, कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और लौटे मजदूरों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने की बात हुई। मगर इन प्रयासों में नीति और क्रियान्वयन के बीच खाई रह गई। परिणाम यह हुआ कि 2021 से 2023 के बीच ही हजारों मजदूर फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व मुंबई की राह पकड़ने को मजबूर हो गए। महामारी ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का जो अवसर दिया था, वह गंवा दिया गया।

मजदूरों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव का भी सीधा असर पड़ता है। चीन की सस्ती मजदूरी ने दुनिया भर के बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को और कठोर बना दिया है, जिससे भारत के छोटे उद्योग व निर्माण क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अस्थिरता को और गहरा किया है। जब उद्योगों पर यह दोहरी मार पड़ती है, तो सबसे पहले मजदूरों की मजदूरी कमजोर होती है और उनकी नौकरी पर संकट आता है। अगर राज्य और केंद्र सरकारें इस वैश्विक परिदृश्य में मजदूरों को संरक्षण नहीं देंगी, तो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और गहरी होती जाएगी।

यह त्रासदी आज एक नए रूप में सामने खड़ी है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में बिहार की मतदाता सूची से 64 लाख नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। इनमें से लगभग 22 लाख मृत, 35 लाख प्रवासित और सात लाख दोहरे पंजीकरण वाले बताए जा रहे हैं। यह संख्या कोई मामूली नहीं, बल्कि बिहार के कुल मतदाताओं का लगभग आठ प्रतिशत है। सवाल यह है कि महामारी में जिन प्रवासी मजदूरों को पहले रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ा, क्या अब उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है? यह मान लेना कि जो मजदूर साल-दो साल बाहर रह गया, उसका बिहार की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं, न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

यह सही है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। मगर असली समस्या तब पैदा होती है, जब गरीब, दस्तावेजहीन और प्रवासी मजदूर इस प्रक्रिया की भेंट चढ़ जाते हैं। दिल्ली और मुंबई में काम करने का मतलब यह नहीं कि वे अब बिहार के नागरिक नहीं रहे। लोकतंत्र का असली सौंदर्य यही है कि इसमें सबसे गरीब, सबसे वंचित और सबसे उपेक्षित नागरिक की आवाज भी उतनी ही ताकत रखती है, जितनी सबसे अमीर और प्रभावशाली की। मगर प्रवासी मजदूर पहले शहरों में अदृश्य रहे, फिर महामारी में भूख और मौत के शिकार बने, और अब यदि उन्हें वोट देने के अधिकार से भी बेदखल कर दिया गया, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर गहरी चोट होगी।

ऐसे माहौल में राहुल गांधी की हाल की वोटर अधिकार यात्रा एक सकारात्मक पहल के रूप में सामने आती है। इस यात्रा में उन्होंने साफ कहा कि प्रवासी मजदूर और गरीब तबका महज श्रम शक्ति नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ हैं। उनका संदेश कि 'हर नागरिक का वोट, उसकी सबसे बड़ी ताकत है', उन लाखों लोगों की पीड़ा से सीधे जुड़ता है, जिनको आज मतदाता सूची से बाहर किए जाने का खतरा है। इस अभियान को यह तथ्य और प्रभावी बनाता है कि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, 'इंडिया' ब्लॉक की साझा ताकत उनके साथ खड़ी है। यह यात्रा लोकतंत्र के उस बुनियादी मूल्य की याद दिलाती है कि सत्ता का असली मालिक नागरिक ही है।

पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी और बाबा साहब को माल्यार्पण के बाद हुई रैली ने 'इंडिया' ब्लॉक की व्यापक एकता को पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसमें कांग्रेस, राजद, सपा के साथ माले, सीपीआई, सीपीएम व अन्य वामदल, विकासशील इंसान पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, एनसीपी-एसपी, शिवसेना और तमाम सहयोगी दल मौजूद थे और सभी ने साफ कर दिया कि मतदाता अधिकार की रक्षा में पूरा विपक्ष एकजुट है।

राहुल गांधी की यात्रा ने मतदाताओं की जागरूकता के साथ-साथ रोजगार का मुद्दा भी बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया। इस यात्रा ने दिखाया कि लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का हक भी है। मताधिकार को सुरक्षित करने के लिए 'इंडिया' ब्लॉक तो एकजुट होकर खड़ा है ही, एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दबे स्वर में इस मांग का समर्थन करने लगे हैं। यह संकेत है कि मतदाता अधिकार अब किसी एक दल का नहीं, बल्कि जनता का साझा मुद्दा बन गया है।

जाहिर है, बिहार का यह चुनाव केवल सत्ता की बाजी नहीं है। यह लोकतंत्र की साख की भी परीक्षा है। महामारी में जो मजदूर पहले भूख और पैदल यात्रा की त्रासदी झेल चुके हैं, अब यदि उन्हें मतदाता सूची से भी बेदखल किया जाएगा, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर गहरी चोट होगी। सरकार को चाहिए कि कौशल व रोजगार योजनाओं की सच्ची समीक्षा करे और प्रवासियों को गांव-कस्बे में टिकाऊ काम दिलाने का प्रयास करे। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर न हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है- हर नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी। और अगर यह हिस्सेदारी छिन गई, तो न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अग्नि-5 : भारतीय उद्यम और पराक्रम की वैश्विक मुनादी

संजय बनर्जी | रिटायर्ड कर्नल

भारतीय उद्यम और पराक्रम के प्रकाश से हमारा पूर्वी क्षितिज उस वक्त जगमगा उठा, जब 20 अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत मिसाइल परीक्षण रेंज से भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। अब्दुल कलाम द्वीप से जब यह मिसाइल दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी, तब इसके भारतीय निर्माता वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ दुनिया भर की निगाहें प्रक्षेपण पथ पर टिक गईं, क्योंकि इससे पहले भारत ने नोटम जारी किया था। नोटम दरअसल हवाई क्षेत्र के साथ समुद्री जहाजों के लिए जारी किया जाता है, ताकि इस दौरान कोई विमान या जहाज संबंधित क्षेत्र में न आए।

अग्नि-5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है और इसका प्रक्षेपण भारत की 'स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड' के तत्वावधान में किया गया। अग्नि-5 के सफल परीक्षण के साथ भारत के आग्नेयास्त्र भंडार में एक और शक्तिशाली और घातक अस्त्र शामिल हो गया है। पृथ्वी शृंखला और अग्नि-2 जैसी विभिन्न सामरिक और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद भारत ने अग्नि-5 नामक आईआरबीएम (मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल) बना ली है। हालांकि, अग्नि-5 की सटीक मारक क्षमता अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बाकी सभी आईआरबीएम की मारक दूरी आमतौर पर 3,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर के बीच होती है, जो काफी हद तक स्फोटक शीर्ष यानी मुखास्त्र के वजन पर निर्भर करती है। मुखास्त्र का वजन बढ़ने पर मारक सीमा कम हो जाती है।

दुनिया सोच रही है कि भारत आगे क्या करेगा, तो अग्नि-6 का इंतजार कीजिए। यह एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी।

इस मिसाइल का विकास स्वदेशी स्तर पर भारत में ही किया गया है। इसके सभी प्रमुख अंग मसलन- तीन चरणों में ईंधन सिलिंडर को सक्रिय करने वाली प्रणाली, परिवहन एवं मार्गदर्शन प्रणाली और हथियार भारत में निर्मित हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। इसकी परिवहन और मार्गदर्शन प्रणाली अत्यधिक जटिल एवं परिष्कृत है, जो भारतीय उपग्रह प्रणालियों से डाटा और इनपुट लेती है। यह विशेषता अग्नि-5 को लंबी दूरी तक अचूक मार करने वाला शक्तिशाली आग्नेयास्त्र बनाता है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु, दोनों तरह के हथियारों को ले जा सकती है।

अग्नि-5 का हमारे अस्त्रागार में शामिल होना, देश की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे निकटतम पड़ोसियों को जरूर सावधान हो जाना चाहिए। यदि भारत को मजबूर किया जाता है या इसके अस्तित्व को चुनौती मिलती है, तो ऐसी स्थिति में अग्नि-5 को सहयोगी मारक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एकीकृत वायु रक्षा कमान एवं नियंत्रण प्रणाली की कमियों को दूर कर उसे और मजबूत कर सकता है। अग्नि-5 की मारक दूरी यदि 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इसके परिष्कृत व हल्के मुखास्त्रों के निशाने पर तुर्किये, यूरोप, रूस के कुछ हिस्से, जापान व ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी जलक्षेत्र सहित पूरे एशिया के देश आसानी से आ सकते हैं। इसकी उच्च-गुणवत्ता वाली लक्ष्य भेदन क्षमता और इसकी परिवहन मार्गदर्शन प्रणाली देश को मिसाइल महाशक्ति बनाती है, जो परमाणु एवं अन्य खतरों का प्रभावी रूप से मुकाबला करने में सक्षम हो गया है।

जाहिर है, भारत की सबसे लंबी दूरी की ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की संख्या व तैनाती का फैसला सर्वोच्च राजनीतिक निकाय सीसीएस (कैबिनेट सुरक्षा समिति) और स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाएगा, जो स्वाभाविक रूप से एक गोपनीय विषय है और रहना भी चाहिए।

अगर दुनिया यह सोच रही है कि भारत आगे क्या करने वाला है, तो अग्नि-6 का इंतजार कीजिए। यह एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो दुनिया के हर कोने तक मारक क्षमता रखेगी। तथाकथित महाशक्तियों और उनके द्वारा समर्थित दुष्ट राष्ट्रों के पास पहले से ही आईआरबीएम व आईसीबीएम मौजूद हैं। सिर्फ उन्हें ही बैलिस्टिक मिसाइलों के बल पर सत्ता और सुरक्षा का सुख क्यों भोगने देना चाहिए?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सिर्फ पूजा-पाठ नहीं अध्यात्म

मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है और उसका वास्तविक संचालक मन है। जब मन की दिशा सकारात्मक और ईश्वर-उन्मुखी होती है, तब जीवन केवल आत्मसुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की ओर प्रवाहित होता है। यदि हम अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित रख दें, तो यह समाज को असंतुलन और अशांति की ओर ले जाता है।

अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ या साधना तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक स्वरूप कहीं व्यापक और गहरा है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत कर आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, तभी वह अध्यात्म कहलाता है। यह साधना हमें भीतर से ऊंचा उठाती है, हमारे मन की उच्च आकांक्षाओं को पोषण देती है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। अध्यात्म बताता है कि मनुष्य के भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी मौलिक वृत्तियां अंतर्निहित हैं, और इनको सही दिशा देना ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए।

इतिहास साक्षी है कि जब-जब समाज ने अध्यात्म की अनदेखी की और केवल स्वार्थपूर्ण चिंतन को अपनाया, तब-तब उसने संघर्ष, विनाश और संकट का सामना किया। व्यक्तिगत सुख की होड़ ने मानव समाज को कभी स्थायी शांति नहीं दी, बल्कि अशांति और पीड़ा को ही जन्म दिया। जब तक पृथ्वी पर स्वार्थ की मानसिकता विद्यमान रहेगी, तब तक मानवता को संकट झेलना ही पड़ेगा। इसके विपरीत, जब चिंतन सामूहिक कल्याण और सकारात्मकता की दिशा में होता है, तब मानव समाज सुख और संतुलन से भरा जीवन जीता है।

मनुष्यत्व का वास्तविक पथ तभी संभव होता है, जब हम अध्यात्म को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। आत्मसुख तत्व हमें सीमित कर देता है, जबकि सम-समाज तत्व, यानी सामूहिक कल्याण हमें महानता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन्होंने सामूहिक कल्याण को अपनाया, वही मानवता के सच्चे उपासक और समाज के पथ-प्रदर्शक बने। अध्यात्म हमें सिखाता है कि मनुष्य का शरीर केवल भौतिक उपभोग का साधन नहीं, बल्कि परमपुरुष की ओर अग्रसर होने का माध्यम है। जब साधना द्वारा मन ईश्वरोन्मुखी बनता है, तब मनुष्य सच्चे अर्थों में मानवता का पुजारी बनता है।

मनुष्यत्व का वास्तविक पथ तभी संभव होता है, जब हम अध्यात्म को जीवन का केंद्र बनाते हैं। आत्मसुख तत्व हमें सीमित कर देता है, जबकि सम-समाज तत्व महानता की ओर ले जाता है।

हम मानव शरीर के अधिकारी थे, इसलिए हमें यह मिला और इसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हम अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित न रखकर सामूहिक कल्याण और ईश्वर की ओर ले जाएं। वास्तव में, यही मानवता का पथ है और यही अध्यात्म का सच्चा संदेश।

श्री श्री आनन्दमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

आज विधानमंडलों और संसद में चर्चा-संवाद, भाषा, मर्यादा के गिरते स्तर से हम चिंतित हैं। ऐसे में, विधायी समितियों की भूमिका अति-महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी यह विशेषता है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं, इनमें हमारा दृष्टिकोण साझा होता है।

अनुलोम-विलोम
भारत-चीन संबंध

दोधारी तलवार पर चलने जैसी दोस्ती

भारत और चीन का रिश्ता जितना पुराना है, उतना पेचीदा भी। कभी सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बौद्ध धर्म की साझी विरासत इनको करीब ले आई, तो कभी सीमा विवाद और युद्ध ने गहरी खाई बना दी। इतिहास गवाह है कि यदि भारत और चीन मिलकर चलें, तो आधी दुनिया की आबादी को समृद्धि का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर टकराएं, तो एशिया और विश्व की शांति डगमगा सकती है। आजादी के शुरुआती वर्षों में जब भारत ने पंचशील सिद्धांतों और 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब यह उम्मीद थी कि दो बड़े पड़ोसी मिलकर एशिया का भविष्य बदल देंगे। मगर 1962 का युद्ध इस विश्वास की नींव हिला गया। तब से अब तक सीमा पर शांति कभी स्थायी नहीं हो पाई। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दे बार-बार रिश्तों में तनाव भरते रहे।

हाल के वर्षों में 2020 की गलवान घाटी की घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। भारतीय जवानों की शहादत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन की विस्तारवादी सोच आज भी कायम है। उसके बाद भारत ने कई चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाए और व्यापारिक रिश्तों को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन यह भी सच्चाई है कि चीन से पूरी तरह अलग होना संभव नहीं हो पाया। आर्थिक मोर्चे पर चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अरबों डॉलर का कारोबार दोनों के बीच होता है, पर यह संबंध बराबरी का नहीं है। भारत चीन से कहीं अधिक आयात करता है और निर्यात बहुत कम। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औद्योगिक कच्चा माल और दवाओं के उत्पादन में चीन की पकड़ इतनी गहरी है कि भारत चाहकर भी एक झटके में उससे मुक्त नहीं हो सकता। यही वजह है कि सुरक्षा के स्तर पर संदेह रखने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूरी में सहयोग निभाना पड़ता है।

चीन की विदेश नीति हमेशा विस्तारवाद की छाया में रही है। पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ रिश्ते भारत को असहज करते हैं। आतंकियों को बचाने के लिए चीन का संयुक्त राष्ट्र में अड़ जाना हो या पाकिस्तान में सीपीईसी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, ये सब भारत की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करते हैं। यही नहीं, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती देने की कोशिश भी चीन करता है। ऐसे में, यही कहना सही होगा कि भारत-चीन संबंध दोस्ती और अविश्वास की दोधारी तलवार की तरह है। उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक होगा।

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप', टिप्पणीकार

चीन के साथ रिश्ते मजबूत होने चाहिए

चीन एक साम्यवादी देश है और उसका पूरा तंत्र सत्ता द्वारा नियंत्रित है। उसके शासकों के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करना भारत से कहीं अधिक आसान है। इसे उसकी अभूतपूर्व प्रगति से भी समझ सकते हैं, जो उसने पिछले तीन दशकों में हासिल की है। चीन एक विशाल देश है और प्राचीन सभ्यता भी। उसके पास न तो प्रतिभा की कमी है और न साधनों की। ऐसे में, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना हमारे हित में ही होगा। उसकी तकनीकी प्रगति को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अच्छी बात है कि इसके लिए हम भी लगातार प्रयत्नशील हैं। गलवान में भले ही उसके साथ हमारा मनमुटाव हुआ, लेकिन समय के साथ वह शांत भी हो गया। चीन ने वैश्विक हालात को देखते हुए भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का मन बनाया है, जो हमारे लिए भी फायदेमंद है। चूंकि क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और राष्ट्रीय हितों को भारत प्राथमिकता देता रहा है, इसलिए चीन के साथ अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक और मोदी-जिनपिंग मुलाकात के बाद संभावना यही है कि दोनों देशों का आपसी सहयोग और आगे बढ़ेगा।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

कूटनीति का सिद्धांत कहता है कि कोई हमारा स्थायी दोस्त नहीं और कोई स्थायी दुश्मन नहीं। कहने का अर्थ है कि जो आज हमारा दुश्मन है, वह कल हमारा दोस्त भी बन सकता है। चीन के संबंध में यही बात कही जा सकती है। बेशक, उसके साथ हमारे रिश्ते बनते-बिगड़ते रहे हैं, लेकिन उससे संबंध पूरी तरह तोड़ लेना उचित नहीं, अलबत्ता जब भी मौका मिले, हमें आपसी रिश्तों को बढ़ाने का प्रयास ही करना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी हद तक ऐसा ही किया। चूंकि चीन को अभी भारत जैसे बाजार की जरूरत है, इसलिए मौके का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। इसका एक और लाभ हमें मिलेगा। अगर भारत और चीन में नजदीकी बढ़ती है, तो इसका एक अर्थ होगा- बीजिंग और इस्लामाबाद में दूरी। यह भारत के हित में है, खासतौर से यह देखते हुए कि बीते कुछ वर्षों में चीन के कारण ही रूस और पाकिस्तान में नजदीकी बढ़ी है। क्षेत्रीय समीकरण को साधने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में स्थिरता हासिल करने के लिए हमें चीन के साथ कदम बढ़ाना ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि चीन भी अपनी जरूरतों के लिए भारत के साथ आना चाहता है। पारस्परिक जरूरतों पर आधारित ऐसे रिश्ते टिकते भी हैं।

स्वाति, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • बुधवार • 3 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

मन एक भीरु शत्रु है, जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है।

\- प्रेमचंद

विकास की नींव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की उत्पादक यात्रा पर हैं। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन सहित विश्व नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों का स्वागत करता है और यूक्रेन संघर्ष को यथा शीघ्र समाप्त करना मानवता का आह्वान है। यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत ने दशकों से विशेष मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं, जो भविष्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने इन संबंधों को दलगत राजनीति से ऊपर बताया और अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त बताया। पुतिन ने रूस-यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के प्रयासों की सराहना की और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों की भी आलोचना की। रूस हमेशा से भारत का मुखर समर्थक रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्यता मिलने का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी तेल और हथियार खरीदने पर भारत को दंडित करने के लिए 50 फीसद टैरिफ लगाया है,जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। भारत और रूस, दोनों के बीच लगभग पंद्रह साल पहले शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी के आधार पर द्विपक्षीय संबंध विकसित हो रहे हैं। इस मुलाकात को ट्रंप को सीधा चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत पुतिन की युद्ध मशीनरी को वित्त-पोषित कर रहा है और रूसी ऊर्जा की बिक्री से भारी मुनाफा भी कमा रहा है जबकि भारत साफ कर चुका है कि रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख कर की गई है। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। देश के ऊर्जा आयात मास्को की हिस्सेदारी 40 फीसद है। बेशक, भारत अपने दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का बचाव करते हुए कहता रहा है कि हम अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देख सकते। इस बैठक को अमेरिका कैसे देखता है, से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि व्यापार असंतुलन को सुधारने के प्रति सकारात्मक रणनीति बनाई जाए और व्यापार में विविधता लाने के प्रयास किए जाएं। भारत, चीन और रूस की इन उत्पादक बैठकों को देख कर अमेरिका की त्योरियां चढ़ने की अब कोई फिक्र करता नहीं नजर आ रहा।

विनिर्माण क्षेत्र में सुधार

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त माह में 17 वर्ष में सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एचएसबीसी की मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी के मुताबिक, यह रिपोर्ट चार सौ ज्यादा विनिर्माताओं के एक समूह में क्रय प्रबंधकों को भेजे गए सवालों के जवाबों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौसमी रूप से समायोजित विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) बीती जुलाई के 59.1 से बढ़ कर अगस्त महीने में 59.3 के स्तर पर जा पहुंचा। भंडारी के मुताबिक, यह बढ़त पिछले साढ़े 17 वर्ष में परिचालन स्थितियों में सबसे तेज सुधार को दर्शाती है। माना जा रहा है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्वस्थ मांग की स्थिति के चलते भारत के विनिर्माण क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल की जा सकी। बेशक, यह उत्पादन क्षेत्र में तेज विस्तार के दम पर मुमकिन हुआ है। जुलाई माह में नये ऑर्डर जुलाई माह में मिले ऑर्डरों के बराबर ही बढ़े, लेकिन यह वृद्धि भी 57 महीने में सबसे तेज रही। रिपोर्ट के मुताबिक, रोजगार के मोर्चे पर भी उत्साहवर्धक स्थिति रही। अगस्त महीने में रोजगार लगातार 18वें महीने बढ़ा। हालांकि नवम्बर, 2024 के बाद यह सबसे कम है। इस बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून में अपेक्षा से अधिक 7.8 प्रतिशथ की दर से बढ़ी जो पांच तिमाहियों में सबसे तेज गति है। बेशक, अर्थव्यवस्था की जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि उच्च स्तर की है, और खासी उत्साहजनक है, लेकिन यह आत्मसंतुष्टि का सबब नहीं बननी चाहिए। इसलिए कि यह महंगाई में नरमी और ट्रंप प्रशासन के शुल्क युद्ध के बाद निर्यात बढ़ने के कारण हुई है। कह सकते हैं कि जीडीपी में यह वृद्धि मजबूत अंतर्निहित मांग का संकेत नहीं है, और इसे कम मुद्रास्फीति और निर्यात में बढ़त से बढ़ावा मिला है। आने वाले समय में इसमें गिरावट का रुख दिखलाई पड़ सकता है। ट्रंप टैरिफ का असर सितम्बर के बाद दिखाई देगा और जिसके चलते तीसरी तिमाही में वृद्धि दर तेजी से घटेगी। यह 6 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है, और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यह और घट कर 5.6 प्रतिशत तक रह सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बना व्यापार अवरोध है, जो अभी जारी है, और आगे भी जारी रह सकता है। बहरहाल, पीएमआई में सुधार का मतलब है कि उत्पादन गतिविधियों में विस्तार दर्ज हो रहा है, जो निश्चित ही उत्साहवर्धक है।

अकेलापन/भूपेश दीक्षित

सामाजिक जुड़ाव ही संजीवनी

तेज रफ्तार, कृत्रिम और डिजिटल होती दुनिया में इंसान तेजी से आगे तो बढ़ रहा है किंतु आधुनिक, आभासी और रील वाली जीवन शैली में चुपके से अकेलापन का भी शिकार हो रहा है। अकेलापन एक गंभीर जनस्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य संकट बन कर हमारे तन-मन पर भारी पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामाजिक जुड़ाव आयोग द्वारा 2025 में जारी 'अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक' रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014-23 के बीच दुनिया के हर 6 में से 1 व्यक्ति ने स्वयं को अकेला पाया; किशोरों में यह अनुपात 20.9 और युवा वयस्कों में 17.4 पाया गया। रिपोर्ट अकेलेपन को महज भावनात्मक उदासी नहीं, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह, अवसाद और डिमेंशिया सरीखी बीमारियों से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट घोषित करती है। रिपोर्ट के अनुसार अकेलेपन के संकट का ठोस आर्थिक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अकेलेपन के कारण होने वाले उत्पादकता ह्रास, चिकित्सा व्यय और देखभाल खर्च मिला कर दुनिया पर अरबों डॉलर का भार डाल रहे हैं।

आधुनिक मनोविज्ञान हमें तीन महत्त्वपूर्ण सीख सिखाता है। पहली, आत्मीय संबंध पोषण और व्यायाम जितने ही जरूरी हैं। दूसरी, संकट में साथ निभाने वाले रिश्ते व्यक्ति ही नहीं, समाज को भी पुनर्जीवित करते हैं, और तीसरी, अकेलापन व्यक्तिगत दोष नहीं है; यह सामाजिक संरचनाओं को व्यवस्थित करके उपचारित करने योग्य है। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति पर अमल करते हुए सामुदायिक पार्क, सार्वजनिक परिवहन, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र, स्कूलों, कार्यालयों में भावनात्मक समर्थन कार्यक्रम और डिजिटल मंचों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो हम वह धरातल बना सकते हैं, जहां अकेलेपन से जूझता व्यक्ति अपनी समस्या का निदान पाकर स्वस्थ समाज और स्वस्थ दुनिया की संरचना में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कहने का सार यह है कि संबंधों में बेहतर निवेश करके दीर्घायु जीवन, बेहतर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य और मजबूत समुदाय का निर्माण कर अकेलेपन की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

विचारधारा की लड़ाई

उपराष्ट्रपति चुनाव

अवधेश कुमार

भाजपा नेतृत्व वाले राजग के सीपी राधाकृष्णन के विरुद्ध इंडिया उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा ने संघ पृष्ठभूमि वाले को उम्मीदवार बनाया जबकि हम ऐसे न्यायमूर्ति को सामने लाए हैं, जिनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है। इस तरह कांग्रेस ने इसे विचारधारा से जोड़ने की राजनीति की है। इंडिया में साफ था कि किसी राजनीतिक दल या वैसे चेहरे के पक्ष में पूरे समूह का वोट सुनिश्चित मानना कठिन होगा। जस्टिस रेड्डी भी दक्षिण के हैं, और संयुक्त आंध्र से होने के कारण विपक्ष की सोच है कि भाजपा के सहयोगियों तेलुगूदेशम, जन सेना के साथ तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के सामने दुविधा पैदा होगी। दोनों सदनों के अंकगणित को देखें लोक सभा की प्रभावी सदस्य संख्या 542 और राज्य सभा की 240 है तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या हुई 782। राजग की 422 संख्या के अनुसार राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना प्रायः निश्चित है।

आइए, अब उम्मीदवारी के पीछे की रणनीति को समझें। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व में विवादों का स्थान नहीं रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पूर्व झारखंड के भी राज्यपाल रहे तथा इसी बीच कुछ समय के लिए तेलंगाना और पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा। लगातार जनता के बीच रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई राजनीतिक विवाद न होना उनकी व्यावहारिक विवेकशीलता का प्रमाण है। वह 1998 और 1999 में दो बार तमिलनाडु के कोयंबटूर से लोक सभा सांसद रह चुके हैं।

इसलिए संसदीय प्रणाली से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। उनका राजनीतिक कैरियर लगभग पांच दशक का है। तमिलनाडु में भाजपा के सचिव और अध्यक्ष रह चुके हैं। जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे और 2007-11 तक सुप्रीम कोर्ट में। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने जब सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जातीय सर्वेक्षण का फैसला किया तो उसकी रिपोर्ट के लिए सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में ही समिति बनाई थी। इस तरह कांग्रेस के साथ उनका संपर्क था। हालांकि जब वे गोवा के लोकायुक्त थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था। उस समय उनकी नियुक्ति भाजपा सरकार की ओर से हुई थी और इसलिए कांग्रेस में उन्हें पक्षपाती माना था।

हालांकि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें नागरिक स्वतंत्रता का झंडा उठाने वाला न्यायाधीश कहा है। छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के विरुद्ध जनता के सलवा जुडूम संघर्ष को जस्टिस रेड्डी ने असंवैधानिक

करार देकर प्रतिबंधित किया था। इस फैसले की तब से आज तक आलोचना होती रही है क्योंकि इसके तहत जनता की अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा द्वारा इन्हें नष्ट करने वालों के विरुद्ध संघर्ष का अधिकार छीना गया था। तो इसका संदेश क्या हो सकता है? शीर्ष स्तर पर न्यायाधीश की योग्यता छोड़ दें तो राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस या किसी पार्टी के समर्थकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं आदि के बीच इसका कोई विशेष संदेश नहीं गया होगा।

कांग्रेस ने पिछली बार जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अपनी नेत्री मारग्रेट अल्वा को खड़ा किया था। सो, यह दावा नहीं कर सकते कि ऐसे पद के लिए राजनीति से परे हटकर विचार करते हैं। लगता है कि विपक्षी दलों के मत दूसरी ओर जाने से रोकने को रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों और व्यवहारों से तमिल बनाम अन्य, उत्तर बनाम दक्षिण के भेद को समाप्त करने के लिए सतत कोशिश करते रहे हैं। संपूर्ण भारत के साथ तमिल संस्कृति और वहां के आस्था स्थलों के जुड़ाव को अलग-अलग तरीकों से रेखांकित करते रहे हैं। काशी तमिल संगम तथा महत्त्वपूर्ण तमिल ग्रंथों के अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद आदि से तमिल राजनीति के उत्तर-दक्षिण, आर्य-द्रविड़, तमिल-गैर-तमिल जैसी विभाजनकारी राजनीति का उत्तर देने की भी प्रभावी कोशिश करते रहे हैं। भाजपा तमिलनाडु में अपना प्रभावी अस्तित्व बनाने के लिए सक्रिय है। इस दृष्टि से राधाकृष्णन का तमिल और पिछड़ा होने का राजनीतिक अर्थ समझ में आता है। दिन-रात भाजपा के विरुद्ध बयान देने वाले शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि उनका अविवादित व्यक्तित्व है। झारखंड से भी उनके बारे में यही आवाज है। वैसे राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का भाजपा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संदेश दूसरे हैं। पहले सत्यपाल मलिक और बाद में जगदीप धनखड़ के अनुभव से सीख लेते हुए लगता है कि भाजपा पूरी तरह परीक्षित नेता को ही महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लाने की नीति की ओर अग्रसर है। पिछले लोक सभा चुनाव में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के असंतोष के पीछे यह प्रमुख कारण था जिसकी क्षति भाजपा को उठानी पड़ी थी।

राधाकृष्णन की पूरे राजनीतिक जीवन में वैचारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रही है। कोयंबटूर में 1997 के दंगों के बीच उनकी भूमिका को हिन्दू संगठनों ने काफी सराहा था। जिन लोगों को पिछली सदी के अंतिम दशक में तमिलनाडु में बढ़ते मुस्लिम कट्टरवाद, दंगों और आतंकवाद की जानकारी है, वे उनके कार्य को भली-भांति समझते हैं। भाजपा के शुद्ध वैचारिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के पक्ष में संपूर्ण राजग का एकजुट होना साबित करता है कि नरेन्द्र मोदी द्वारा सत्ता संभालने के बाद राजनीति भाजपा के संदर्भ में कहां से कहां पहुंच गई है। यह राजग के भीतर वैचारिक द्वंद्व की संभावनाओं को तत्काल खारिज करने वाला संदेश है।

महाराष्ट्र में भी शिवसेना शिंदे और राकांपा अजीत पवार द्वारा किसी तरह के विचलन की संभावना नहीं दिखती। चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में भूल कर दी थी, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। काफी संघर्ष के बाद वे सत्ता में लौटे हैं। इस स्थिति में वे विपक्ष का साथ दे देंगे, कल्पना कठिन है। इसके उलट क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात का असर हो सकता है? कांग्रेस द्वारा इस विचारधारा की लड़ाई बताने के बाद अगर भाजपा की वैचारिक प्रतिबद्धता वाले उम्मीदवार के पक्ष में दूसरी ओर का कुछ वोट भी आता है तो यह भाजपा नेतृत्व के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वस्तुतः यह भारत की भावी राजनीति के लिए दिशा संकेतक जरूर होगा।

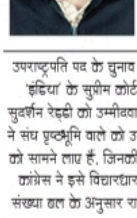

(लेख में विचार निजी हैं)

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राजग के सीपी राधाकृष्णन के विरुद्ध 'इंडिया' के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा ने संघ पृष्ठभूमि वाले को उम्मीदवार बनाया जबकि हम ऐसे न्यायमूर्ति को सामने लाए हैं, जिनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है। इस तरह कांग्रेस ने इसे विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि संख्या बल के अनुसार राधाकृष्णन का चुना जाना प्रायः निश्चित है

इम्यून सिस्टम को बूस्ट और पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है

- रसोई का मुख्य मसाला लौंग न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि अपने आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों के कारण सेहत के लिए भी वरदान है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, पाचन तंत्र को दुरुस्त करने और दांतों की समस्याओं में राहत देते हैं
- आयुर्वेदाचार्य गर्मियों में लौंग को सौंफ, मिश्री या गुलकंद जैसे शीतल खाद्य पदार्थों के साथ लेने की सलाह देते हैं ताकि इसकी ऊष्णता या गर्मी संतुलित हो। आयुर्वेद के अनुसार, लौंग साल भर फायदेमंद है बशर्ते इसका सेवन संतुलित और सही तरीके से हो

(मीडिया इनपुट्स)

भारत यदि चीन के साथ बड़े निवेश आमंत्रित करके उसके साथ आर्थिक संबंध प्रगाढ़ करता है, तो भारत के लिए समझदारी की बात होगी कि आरसीईपी में शामिल होकर अपने निर्यात बढ़ाने के लिए सबसे बड़े निर्यात जोन में अपनी संभावनाएं तलाशे। चीन इस मामले में 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयोगी' के रूप में भारत की सहायता कर सकता है।

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

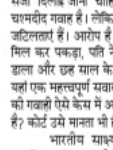

कितनी विश्वसनीय बच्चे की गवाही?

निक्की हत्याकांड **कमलेश जैन**

दहेज का लेन-देन भारतीय समाज में दशकों से हो रहा है। हाल में निक्की भाटी हत्याकांड अपनी वीभत्सता के चरम पर पहुंच गया। इस घटना से समूचा देश सन्न रह गया। हर कोई इस दुखद घटना को लेकर दहेज कानून को कायदे से लागू न किए जाने पर मलाल तो जता ही रहा है, साथ ही जोरदार मांग उठ रही है कि आरोपियों के खिलाफ कानून-सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। इस मामले में छोटा बच्चा चश्मदीद गवाह है। लेकिन बच्चे की गवाही को लेकर कुछ जटिलताएं हैं। आरोप है कि निक्की को पति और सास ने मिल कर पकड़ा, पति ने ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाला और छह साल के बेटे के सामने उसे जला डाला। यहां एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर, एक बच्चे की गवाही ऐसे केस में अदालत के सामने क्या मायने रखती है? कोर्ट उसे मानता भी है या नहीं?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक नाबालिग का बयान तभी विश्वसनीय है जब वह दूसरे प्रकार के सवालों का जवाब सही तरीके से दे सकता हो। सवाल है कि धारा 118 के अंतर्गत क्या कोई बच्चा विश्वसनीय गवाह की श्रेणी में आता है, या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है-कि ऐसी गवाही, यदि विश्वसनीय है, एक तरह की है, जिसमें बार-बार बदलने की प्रवृत्ति नहीं है-तब वह सजा देने लायक ठीक है। इसकी विश्वसनीयता जांचने की जरूरत नहीं है-यानी दूरी गवाही से मिलान करने की जरूरत नहीं है। वह गवाही अपने आप में पूर्ण है।

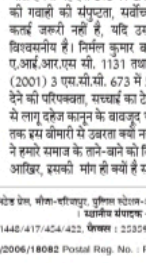

एक विश्वसनीय, एक जैसी और तर्कयुक्त गवाही की संपुष्टि आवश्यक नहीं है। पर नाबालिग की गवाही की संपुष्टि यदि मेडिकल एविडेंस से हो जाती है तो बच्चे की गवाही पूर्णतया विश्वसनीय है। पहले कोई यह जांचता है कि बच्चे की समझदारी किस स्तर की है। क्या वह साधारण बातों को समझता है। आसान सवालों जैसे-माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम, घर का पता ठीक-ठीक बता सकता है-जो पढ़ा है, उसे समझ कर बोल सकता है-और तब यदि बच्चा इस टेस्ट में पास हो जाता है, तभी उसे मुकदमे के बारे में गवाही देने को कहा जाता है। बच्चे को जांचने का नियम है 'वॉयर डायर टेस्ट'। यह एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ है 'वह जो सच है'। बच्चा इसी टेस्ट से गुजारा जाता है। देखा

जाता है कि वह इस टेस्ट पर खरा उतरता है या नहीं? बच्चे की गवाही की संपुष्टता, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कतई जरूरी नहीं है, यदि उसकी गवाही उचित और विश्वसनीय है। निर्मल कुमार बनाम यूपी राज्य (1992) ए.आई.आर.एस सी. 1131 तथा सुदेश बनाम यूपी राज्य (2001) 3 एस.सी.सी. 673 में 5 वर्ष के बच्चे की गवाही देने की परिपक्वता, सच्चाई का टेस्ट किया गया है। 1961 से लागू दहेज कानून के बावजूद भारतीय हिन्दू समाज आज तक इस बीमारी से उबरता क्यों नहीं? धीरे-धीरे इस अपराध ने हमारे समाज के ताने-बाने को बिखेरना शुरू कर दिया है। आखिर, इसकी मांग ही क्यों है समाज में? एक लड़की का पिता उसकी समुचित देखभाल कर एक स्वस्थ, शिक्षित, होनहार लड़की विवाह में वर पक्ष को समर्पित करता है, फिर भी दहेज की चाहत क्यों बढ़ती जा रही है जिसमें लड़के की संपूर्ण परिवार लालच की हदें पार कर देता है।

इसका नतीजा क्या होता है? लड़के वालों को जानना चाहिए कि 'क्राइम नेवर पेज' यानी अपराध कभी फलीभूत नहीं होता। याद रखिए, खून कर कोई नहीं बचता। अकेली लड़की को ससुराल में पूरा परिवार दहेज के नाम पर दानवों की तरह नोच कर खा लेना चाहता है। वे लालच के सामने प्रेम, दया, समान व्यवहार की भावना को दूर-दूर तक दफन कर देते हैं। लड़की की जान तो जाती है, दुर्व्यवहार से पर जो उस पर अत्याचार करते हैं, वे भी खुद को नीचे गिरा रहे हैं। कोई इंसान खुद के साथ सबसे बुरा यही कर सकता है कि वह जानवर के स्तर तक गिर जाए और यह सब कुछ लालच के कारण करता है। यह बर्ताव उसे कुछ पल की खुशी, आनंद या ताकत प्रदान कर सकता है, पर यह पूरे परिवार के लिए त्रासदी का काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक शिकार है, और दूसरा शिकारी। दोनों ही शिकार हैं। लड़की जान से जाती है, तो लड़के का पूरा परिवार जेल की हवा खाता है, परिवार बदनाम हो जाता है, दूसरे लड़के-लड़की का विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है।

समय आ गया है कि लोग इस लालच से बचें, सोच-समझ कर शादी-विवाह करें और एक विश्वसनीय, स्थायी जीवन जीएं और सम्मान के साथ। दहेज की बुराई को कानून की सख्ती से रोकने के प्रयास के साथ जरूरी है कि इस कुरीति के खिलाफ जोरदार जनजागरण किया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब-तब घटती रहती हैं, और हमें सचेत करती हैं कि कहीं न कहीं हमारे प्रयासों में अभी भी कमी है। इसलिए हमें सतत प्रयासरत रहना होगा। समाज में दहेज के प्रति तिरस्कार की भावना पनपना बेहद जरूरी है, जो हमारे प्रयासों से हो पाना संभव है।

(लेख में विचार निजी हैं)

पक्षपात **श्रीराम शर्मा आचार्य**

भगवान ने मनुष्य के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, बल्कि उसे अमानत के रूप में कुछ विभूतियां दी हैं, जिनको सोचना, विचारणा, बोलना, भावनाएं, सिद्धियां-विभूतियां कहते हैं। ये अमानतें इसलिए नहीं दी गई हैं कि इनके द्वारा वह सुख-सुविधाएं कमाए और स्वयं के लिए ऐय्याशी या विलासिता के साधन इकट्ठे करे और अपना अहंकार पूरा करे। ये सारी की सारी चीजें इसलिए उसको दी गई हैं कि इन चीजों के माध्यम से वो जो भगवान का इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है, उसकी दिक्कतें और कठिनाइयों का समाधान करे और उसे अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे। बैंक के खजांची के पास धन रखा रहता है, और इसलिए रखा रहता है कि सरकारी प्रयोजनों के लिए इस पैसे को खर्च करे। उसको उतना ही इस्तेमाल करने का हक है, जितना कि उसको वेतन मिलता है। खजाने में अगर लाखों रुपये रखे हों, तो खजांची उन्हें कैसे खर्च कर सकता है? पुलिस और फौज का कमांडर है, उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं, उसी से काम चलाना चाहिए और बाकी जो उसके पास बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति बंदूक चलाने के लिए मिली है, उसको सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए, जिस काम के लिए सरकार ने उसको सौंपा है। हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ भी विभूतियां, अक्ल और विशेषताएं हैं, वे अपनी व्यक्तिगत ऐय्याशी और व्यक्तिगत सुविधा और व्यक्तिगत शौक-मौज के लिए नहीं हैं, और व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उसको विशेषता दी गई है, उसको उतना बड़ा जिम्मेदार आदमी समझा जाए और जिम्मेदारी उस रूप में निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समुन्नत बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है-निःस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्यार किया। मानव जीवन की विशेषताओं का और भगवान के द्वारा विशेष विभूतियां मनुष्य को देने का एक और भी उद्देश्य है। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले और ये समझ ले कि 'मैं क्यों पैदा हुआ हूं, और यदि मैं पैदा हुआ हूं? तो मुझे अब क्या करना चाहिए?'

रीडर्स मेल

उभर रही है बहुध्रुवीय व्यवस्था

दुनिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। शीत युद्ध के बाद लंबे समय तक अमेरिका को अकेली महाशक्ति माना जाता रहा लेकिन अब बहुध्रुवीय व्यवस्था उभर रही है। भारत इस समय कठिन मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर क्वाड का अहम हिस्सा है, तो दूसरी ओर रूस और चीन के नेतृत्व वाले एससीओ में भी सदस्य है। यह संतुलन साधना आसान नहीं है। पहले अमेरिका भारत को लोकतंत्र का प्राकृतिक सहयोगी बताता था, लेकिन अब ट्रंप खुल कर आलोचना करने लगे हैं। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। यही नहीं, ट्रंप सरकार ने भारत पर ऊंचे टैरिफ भी लगाए हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चीन दौरा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हो गई। भारत यदि संतुलन और साझेदारी की नीति पर डटा रहा, तो आने वाले समय में न केवल एशिया, बल्कि पूरी दुनिया का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। यही तियानजिन सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश है।

समराज चौहान, असम

भारत में लगें ज्यादा उद्योग

एक ओर जहां भारतीय मुद्रा भंडार कम हो रहा है, और अमेरिका और चीन निर्यात करके अच्छी कमाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, और उद्योग और कल-कारखाने बंद हो रहे हैं। भारत में निर्मित वस्तुओं से भारत के ही व्यापारियों को फायदा होगा एवं बेरोजगारी कम होगी। अतः बड़े उद्योगपतियों को अपने निजी स्वार्थ और लाभ की बजाय भारत में ही उद्योग लगाने चाहिए और सस्ते चीनी और विदेशी निर्मित आयातित वस्तुओं का मोह त्याग कर देशहित में देश की आर्थिक उन्नति के लिए आम जनता को भी मेड इन चाइना वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सरकार को भी मेड इन इंडिया के तहत सस्ते कर्ज एवं तकनीकी जानकारी उद्योगपतियों को उपलब्ध करानी चाहिए।

आदित्य सोनी 'सार्थक', धार, मप्र

हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़े

यह पत्र 'प्रशंसनीय पहल' से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं अभियान निस्संदेह सराहनीय है, और इस तरह का अभियान पूरे देश में चलना चाहिए ताकि सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दिया जा सके। दुर्भाग्यवश भारत पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के मामले में सबसे ऊपर आता है तो इस तरह के अभियान से दुपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में जागरूकता आती है, और उन्हें यह अहसास होगा कि हेलमेट कितना जरूरी है, लेकिन इस अभियान के ध्येय की सफलता के लिए सबसे अहम यह है कि हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि यह पता लगे की इस नियम का कड़ाई से पालन हो भी रहा है या सिर्फ यह कागजों तक ही सीमित है, और इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करा जाए कि हेलमेट भी मानकों के अनुसार ही पहना जा रहा है क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोग क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाने वाला या फिर कोई हल्का सा हेलमेट पहन लेते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़े नहीं।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काद्री द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-परियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6764
आर.एन.आई. नं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

आजकल

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफार्मेंसेज से संबद्ध

डिजिटल सर्विस टैक्स की हो वापसी

भारत ने वर्ष 2016 में अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों पर छह प्रतिशत डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया था, लेकिन अमेरिका से चल रही व्यापार वार्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधित बयानों के मद्देनजर इस साल के आम बजट में इसे हटा दिया गया, ताकि ट्रेड डील में आसानी हो सके, लेकिन इस नरमी के बावजूद अमेरिका ने भारत पर मनमाना 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि भारत भी इस टैक्स को वापस लाए, ताकि अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों की कमाई में से अपना वाजिब हिस्सा पा सके

डिजिटल कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता। प्रतीकात्मक

भारत में अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों पर अब कोई डिजिटल सर्विस टैक्स नहीं लगता है। इसे इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेवी को गत दिनों खत्म कर दिया गया था। अब इस टैक्स की चर्चा फिर हो रही है। डिजिटल कानूनों और डिजिटल सर्विस टैक्स की चर्चा के दो अहम कारण हैं। पहला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सनक भरे फैसले के तहत भारत के कई उत्पादों के आयात पर 50 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा किया जाना। हालांकि सरकार टैरिफ की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के प्रयास कर रही है। वह प्रभावित होने वाले भारत के कारोबारी सेक्टर के उत्पादों के लिए दुनिया के नए बाजारों के विकल्प तलाश रही है, लेकिन इस बीच एक विचार यह सामने आया है कि क्यों न भारत भी उन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिक्रियावादी (रेसिप्रोकल) टैक्स या टैरिफ लगाए, जो अपने उत्पाद भारत में बेचती हैं। ऐसे उत्पादों की अच्छी-खासी संख्या है, पर इनमें ज्यादा चर्चा उन अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों की हो रही है, जिनकी भारत में बड़े पैमाने पर उपस्थिति है। जैसे कि आइफोन बनाने वाली कंपनी एपल, सर्च इंजन गूगल, मेटा (फेसबुक), इंस्टाग्राम, एमेजान और नेटफ्लिक्स आदि। भले ही सरकार इन सभी कंपनियों के कारोबारी संचालन पर डिजिटल सर्विस टैक्स नहीं लेने का कानूनी प्रबंध कर चुकी है, लेकिन जब यह फैसला लिया गया था, तो उसका मकसद किसी व्यापारिक समझौते में ट्रंप सरकार की ओर से भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ में नरमी के व्यवहार की उम्मीद करना था। ट्रंप ने न सिर्फ इस लेवी पर भारत के सकारात्मक रवैये की अनदेखी की, बल्कि अनुचित तर्कों के आधार पर टैरिफ थोप दिए। लिहाजा बदली हुई स्थितियों में भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए इन सभी अमेरिकी टेक और डिजिटल कंपनियों पर दोबारा इक्वलाइजेशन लेवी लगाने पर विचार कर सकता है।

डिजिटल सर्विस टैक्स वह टैक्स है, जो सरकारें उन बड़ी अंतरराष्ट्रीय टेक कंपनियों पर लगाती हैं, जिनकी वहां भौतिक (फिजिकल) रूप से मौजूदगी नहीं होती। ये कंपनियां उस देश के बाहर से काम करती हैं। पारंपरिक तौर पर ऐसा कारपोरेट टैक्स किसी कंपनी पर तभी लगता है, जब उसकी उस देश में स्थायी मौजूदगी हो, लेकिन तकनीक (टेक) और डिजिटल कंपनियों के मामले में यह जरूरी नहीं है कि कारोबार करने के लिए वे किसी देश में भौतिक तौर पर उपस्थित हों। लिहाजा उनके बिजनेस को कानूनी प्रविधानों के तहत लाने के लिए अलग नियमों और टैक्सों की जरूरत पड़ती है। इन कानूनों और टैक्सों का उद्देश्य टेक या डिजिटल कंपनियों से सिर्फ कर वसूल करना मात्र नहीं होता है, बल्कि इनकी मदद से डिजिटल कंपनियों की मनमानी और एकाधिकार पर अंकुश लगाना और डिजिटल संसार में अपेक्षित सुधार लाना भी है। इन कानूनों की मदद से डिजिटल सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है और पारदर्शिता लाते हुए डिजिटल सेवाओं के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

सबसे पहले डिजिटल कानूनों को समझना होगा। मिसाल के रूप में यूरोपीय संघ (ईयू) की नियामक स्वायत्तता (रेगुलेटरी आटोनामी) के तहत लागू किए गए डीएसए और डीएमए नामक दो कानूनों को देखा जा सकता है। वर्ष 2023 में ईयू से जुड़े 27 देशों में लागू डीएसए यानी डिजिटल सर्विसेज एक्ट, 2023 के अंतर्गत डिजिटल सेवाएं देने वाले आनलाइन मंचों को इसके लिए बाध्य किया जाता है कि वे अपने प्लेटफार्म पर आने वाले अवैध कंटेंट, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाएंगे और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस कानून के नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार के छह फीसद तक जुर्माना लग सकता है, जो कि एक बड़ी राशि है। यूरोपीय देशों में गूगल, मेटा, एपल, इंस्टाग्राम और एमेजान जैसी कंपनियों को इस कानून की पकड़ में आने से बचने के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। ये कंपनियां वहां अपने प्लेटफार्म पर अवैध कंटेंट डालने वाले यूजर्स की पहचान कर उनके अकाउंट निलंबित करती हैं। शरारतपूर्ण और जानमाल को संकट में डालने वाले खतरों की पहचान कर उन्हें दूर करती हैं। साथ ही अपना डाटा संबंधित देश की सरकारों के साथ साझा करती हैं।

उपभोक्ताओं को विकल्प देने वाला नियमन : इसी तरह डीएमए यानी डिजिटल मार्केट्स एक्ट का उद्देश्य डिजिटल बाजार में किसी भी कंपनी के एकाधिकार को रोकना और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना है। इसमें नियम यह है कि एपल, मेटा और माइक्रोसाफ्ट आदि बड़ी टेक कंपनियों को एप स्टोर पर अपने भुगतान सिस्टम और विज्ञापनों के दावों में पारदर्शिता लानी होगी। उन पर इसके लिए नजर रखी जाती है कि कहीं वे उभरती हुई संभावित प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को खरीद बाजार में एकाधिकार की स्थिति तो नहीं लाना चाहती हैं। उल्लेखनीय है कि इस नियम के उल्लंघन की सूरत में कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार के 20 फीसद तक जुर्माने का प्रविधान कानून में किया गया है।

वैश्विक शक्ति के केंद्र में है डिजिटल अर्थव्यवस्था : दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था वैश्विक शक्ति के केंद्र में है, इसलिए कह सकते हैं कि टेक और डिजिटल कंपनियों का कारोबार और उनके लिए नियम-कायदे बनाने वाले संगठन और सरकारें अब शक्ति संतुलन साधने की प्रभावकारी भूमिकाओं में हैं। ऐसे में यदि टेक-डिजिटल कंपनियों को मनमानी की छूट दी जाती है तो अपने हितों के लिए गड़बड़ी कर सकती हैं। ऐसे में यदि उन पर नियमों-कानूनों का अंकुश नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता हितों से लेकर छोटी-उभरती हुई कंपनियों का संचालन एवं कारोबार ठप्प पड़ सकता है। सिलिकान वैली और यूरोपीय संघ का यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका-यूरोप या शेष विश्व का नहीं है, बल्कि इसमें उपभोक्ता के रूप में पूरी दुनिया के नागरिक शामिल हैं। इसलिए समूचे वैश्विक डिजिटल तंत्र के समुचित और सख्त नियमन की जरूरत है, ताकि इसका विकास सही दिशा में हो सके।

ट्रंप की टैरिफ नीति का सही जवाब

ट्रंप प्रशासन सिर्फ डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएसए) और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (डीएमए) को लेकर चिंतित और आक्रामक नहीं है, बल्कि उसकी मुख्य चिंता वह डिजिटल सर्विस टैक्स है, जिसे कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों ने टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के तहत हाल में हटाया तो है, लेकिन कोई तनातनी बढ़ने पर इसे वापस लागू भी कर सकते हैं। कनाडा ने जब तक अमेरिकी डिजिटल कंपनियों पर से डिजिटल सर्विस टैक्स नहीं हटाया था और इन कंपनियों पर इस टैक्स की पहली किस्त जमा करने का दबाव था, उससे कुछ ही समय पहले ट्रंप के रुख को देखते हुए कनाडाई सरकार ने इसे वापस ले लिया, ताकि उस पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने इस टैक्स को 'खुला हमला' बताते हुए व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत रद कर दी थी और कनाडा से होने वाले आयात पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसी तरह के दबाव में आकर यूरोपीय संघ के देशों ने भी एपल और मेटा जैसी अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की योजना वापस ले ली। ईयू के देश भी आशंकित थे कि कहीं इस टैक्स की वजह से बात बिगड़ न जाए, लेकिन बात सिर्फ कनाडा या ईयू की नहीं है। चूंकि इन अमेरिकी डिजिटल कंपनियों का विस्तार पूरी दुनिया में है, ऐसे टैक्स कहीं भी लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह चुनौती दी है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया, तो अमेरिका उस पर और ज्यादा टैरिफ थोप देगा।

भले ही ट्रंप टैरिफ के चाबुक के बल पर दुनिया भर के देशों पर दादागिरी चला रहे हैं, पर इसका एक सच यह है कि ज्यादातर अमेरिकी डिजिटल कंपनियां किसी देश में अपना दफ्तर खोले बगैर अरबों डालर कमा रही हैं और बदले में उन देशों को ठेंगा दिखा रही हैं। ये कंपनियां अपने आनलाइन प्लेटफार्म पर आने वाले विज्ञापनों और दूसरी सेवाओं को दिखाने के बदले अकूत धन कमाती हैं। इसके अलावा अपने उपभोक्ताओं से जुड़े डाटा से भी कमाई करती हैं। असल में उन उपभोक्ताओं की संख्या और उपस्थिति दिखाकर वे अपने विज्ञापनदाताओं से अतिरिक्त पैसे लेती हैं। इतनी कमाई करने के बावजूद ये संबंधित देशों के साथ उसका जरा भी हिस्सा साझा नहीं करती हैं। इसी के मद्देनजर भारत में 2016 में इन कंपनियों पर छह फीसद डिजिटल सर्विस टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी अथवा समानता कर लगाया गया था, लेकिन अमेरिका से चल रही व्यापार वार्ता और ट्रंप के टैरिफ संबंधित बयानों के मद्देनजर इस साल के आम बजट में इसे हटा दिया गया, ताकि ट्रेड डील में आसानी हो सके, लेकिन इस नरमी के बावजूद अमेरिका ने भारत पर 50 फीसद टैरिफ लगा दिया। इसलिए जरूरी है कि भारत और अन्य देश इस टैक्स को वापस लाएं, ताकि अमेरिकी टेक-डिजिटल कंपनियों की कमाई में से अपना वाजिब हिस्सा पा सकें।

ध्यान रखना होगा कि किसी भी देश में गए बगैर मोटी कमाई करने वाली अमेरिकी टेक कंपनियां ये टैक्स नहीं देना चाहती हैं। इस बारे में अमेरिकी कंपनियों का तर्क है कि वे अपने मूल अथवा मुख्यालय वाले देश में पहले से ही इन सेवाओं के लिए टैक्स चुकाती हैं। ऐसे में अन्य देशों में डिजिटल सर्विस टैक्स लगने पर उन्हें दोहरा कराधान झेलना होगा, लेकिन जब बात समानता के व्यवहार की आती है, तो 50 फीसद टैरिफ जैसे चाबुक का मुकाबला ऐसे ही टैक्स लगाकर किया जा सकता है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

नोबेल शांति पुरस्कार पाने के टोटके

डा. प्रदीप मिश्र

नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं? प्रयास कर रहे हैं, किंतु सफलता नहीं मिल रही है। बाधाएं आ रही हैं। घबराइए नहीं। हमारे टोटके अपनाइए। नोबेल का दरवाजा आपके लिए खुद खुल जाएगा।

पहला टोटका यह है कि आपको दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि दुश्मन भी शर्मा जाएं। ऐसी वाणी बोलिए कि सारे दोस्त दूर हो जाएं। उनके व्यापार में हानि करवा दीजिए। जब यारी-दोस्ती खत्म हो जाएगी, तब आपके जीवन में अखंड शांति व्याप्त हो जाएगी। शांत जीवन देखकर नोबेल आपकी ओर आने का मन बनाने लगेगा।

फिर पत्रकारों के सामने शांति-शांति-शांति का जाप करें। बीच-बीच में बोलें, 'मैंने। सिर्फ मैंने। चारों तरफ शांति कायम की। मैं शांति नहीं लाता तो लोग लड़-लड़कर खत्म हो जाते।' ऐसा, सुबह-दोपहर-शाम, दो-दो बार बोलें। यकीन मानिए, पत्रकार खुद आपका नाम नोबेल के लिए सिफारिश कर देंगे। नोबेल को अपनी ओर शर्तिया आकर्षित करने के लिए घर, दफ्तर, दुकान-हर जगह अपनी नेम प्लेटों पर बड़े अक्षरों से लिखवाइए, 'विश्व शांति दूत'। उसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर वैज डालिए। संसार कहेगा, 'नोबेल पर तो इन्हीं का हक बनता है।'

दुर्दांत लठैत भेजकर अपने पड़ोसी का घर तहस-नहस करवा दें। इसकी वजह बताते हुए कहें कि, 'उसके पास खतरनाक हथियार थे और वह गैरजिम्मेदार भी है। उससे शांति को खतरा था। लठैतों के जरिए मैंने शांति कायम कायम की है।' भले उसके घर पर हथियार के नाम पर चिमटा भी नहीं मिले, पर आपको यही कहना है कि 'मैं शांति दूत, मैंने कायम की, शांति अटूट।' ऐसा करने से नोबेल आपके गले पड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। किसी भूखे-प्यासे सैनिक को घर बुलाकर खाना खिलाइए। उसे भीख भी दें। जिससे उसका मन शांत होगा। नोबेल पुरस्कार देने वाले कहेंगे, 'असल शांति प्रदाता यही है।' और पुरस्कार लेकर वे आपकी ओर दौड़ पड़ेंगे।

इसी तरह के अन्यान्य शर्तिया टोटके जानने के लिए मिलें या लिखें।

पोस्ट

एससीओ की बैठक ने यह भी रेखांकित करने का काम किया कि अंग्रेजी के बिना भी वैश्विक मंच पर संवाद हो सकता है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

एससीओ सम्मेलन के दौरान जिस प्रकार से पुतिन, मोदी और चिनफिंग मिले, वह संकेत है कि अब नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। यह अमेरिका के भ्रष्टाचार और यूरोप की दुर्बलता का नतीजा है।
गैरी कास्परोव@Kasparov63

देश ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इस मंजिल तक पहुंचने में हमें थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन अंततः पहुंच ही गए। अब ईश्वर हमें इस क्षेत्र में उत्कृष्टता का आशीर्वाद प्रदान करें।
रणवीर शौरी@RanvirShorey

भारत में लचर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की दुर्दशा के लिए अक्सर विशाल जनसंख्या को दोष दिया जाता है, पर चीन की आबादी भी तो इतनी ही है, मगर उसने इन मोर्चों पर नए प्रतिमान गढ़े हैं। असल में भारत की समस्या सरकारी बाबुओं की कार्यसंस्कृति से जुड़ी है, जो प्रगति में बाधक बनती गई।
नलिनी@NalinisKitchen

जागरण जनमत कल का परिणाम

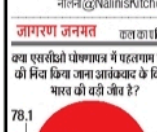

क्या एससीओ घोषणापत्र में पहलगाम हमले की निंदा किया जाना आतंकवाद के विरुद्ध भारत की बड़ी जीत है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या एससीओ के मंच से एक नई वैश्विक व्यवस्था के संकेत मिले हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अमरीका अब दे रहा जातिवाद को खाद,
तेल खरीदी में दिखे उसको 'ब्राह्मणवाद'।
उसको 'ब्राह्मणवाद' छोड़कर नया शिगूफा,
शायद ही संतुष्ट रुष्ट जो बैठे फूफा!
एससीओ के बाद रंग दिखता है फीका,
झेंपा-झेंपा दीख रहा तब ही अमरीका!!
- ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

पंजाब पर असर डालते हरियाणा के फैसले

हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रभावित राज्य के सभी 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इन परिवारों के सदस्य सिख विरोधी दंगों में मारे गए थे। सिख विरोधी दंगों में प्रदेश में लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, तीन रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनने के बाद हरियाणा सरकार ने ऐसे परिवारों के पुनर्वास का जिम्मा लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अकेली यही घोषणा नहीं की है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी दिवस पूरे साल मनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने अपने इस फैसले में विपक्ष को भी शामिल करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा अपने चुनावी वादे के अनुरूप भाजपा सरकार ने पहले चरण में राज्य की करीब 20 लाख महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपये मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया है। हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से महिलाओं को भत्ते की यह राशि मिलनी आरंभ हो जाएगी। राज्य में करीब 46 लाख महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के दायरे में आती हैं। बाकी बची 26 लाख महिलाओं को दूसरे एवं तीसरे चरण में लाडो लक्ष्मी योजना के मासिक भत्ते की राशि प्रदान की जाएगी।

एसवाईएल नहर के निर्माण और पानी के लिए पंजाब के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के बीच हरियाणा सरकार के इन तीन बड़े फैसलों का राज्य में तो भाजपा को लाभ मिलने की संभावना है ही, साथ ही पंजाब में भी फायदा मिलने से इन्कार नहीं किया जा सकता। पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के नाते नायब सिंह सैनी जिस तरह से अपनी सरकार के फैसलों के माध्यम से पंजाब में भाजपा के लिए चुनावी मैदान तैयार करने में जुटे हैं, वह पार्टी की आंतरिक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। नायब सिंह सैनी ने पंजाब के जिलों में आवाजाही बढ़ा दी है। हरियाणा एवं चंडीगढ़ से सटे जिलों में उनके कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं। पंजाब के उद्योगपतियों से मिलने का सिलसिला जारी है। पंजाब के कलाकारों के साथ नायब सैनी नियमित बैठकें कर रहे हैं, जो भाजपा की पंजाब में चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने जाते हुए। फाइल

पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पंजाब में भाजपा को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसने 18.57 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। विधानसभा चुनाव में मुकेरियां और पठानकोट सिर्फ दो सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत 6.60 तक ही पहुंच पाया था। पंजाब में संगठन को मजबूत करना और लोगों से जुड़ना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहां 2017 से भाजपा सत्ता से बाहर है। अब शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन भी नहीं रहा है। इस गठबंधन के नहीं होने का नुकसान दोनों दलों को हो रहा है। दोनों दल चाहते हैं कि गठबंधन फिर से हो, लेकिन पंजाब भाजपा के कुछ नेता इस पक्ष में नहीं हैं कि ज्यादा दिनों तक शिरोमणि अकाली दल पर निर्भर रहा जाए। हालांकि इसके लिए पार्टी को आंतरिक तौर पर मजबूत करना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयास भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।

एक के बाद एक पंजाब की राजनीति पर असर डालने वाले फैसले लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरह भाजपा के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, उससे विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर, मानसा, बठिंडा, संगरूर, पटियाला एवं मोहाली जिले हरियाणा से सटे हुए हैं। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जिले पंजाब के जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पंजाब की राजनीति पर सिख दंगों का असर आज भी दिखाई देता है। गुरु तेग बहादुर साहिब ने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जींद, अंबाला, चीका और रोहतक में चरण रखकर इस भूमि को पवित्र किया था। ऐसे में हरियाणा सरकार के फैसलों का कहीं न कहीं पंजाब कनेक्शन होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पंजाब में आप ने चुनाव से पहले महिलाओं को हर माह 1,100 रुपये और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपये महीना देने की घोषणा की थी। दोनों सरकारों का अधिकतर कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस योजना को लागू करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। ऐसे में हरियाणा के इन फैसलों का सीधा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है।

मंथन

अरविंद कुमार मिश्र
लोकनीति विश्लेषक

इस्पात उद्योग को मिले मजबूती

भारत को स्टील के वैश्विक बाजार में व्यापक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए घरेलू बाजार को मजबूत करने के साथ नए बाजार तलाशने होंगे

अलग-अलग नीतिगत पहल से भारत इस्पात यानी स्टील के वैश्विक बाजार में अपनी धाक बढ़ा रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति लागू की है। रसोई से लेकर सड़क, पुल, बंदरगाह, सैन्य उपकरण और उपग्रहों को तैयार करने में इस्पात मुख्य घटक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्टील की भूमिका ठीक वैसी ही होती है जैसी शरीर में हड्डियों की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। वर्तमान में हमारी इस्पात उत्पादन क्षमता 144 मिलियन टन से अधिक है। 2030 तक 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। अभी देश में प्रति व्यक्ति स्टील खपत लगभग 100 किलोग्राम है, जिसे इस दशक के अंत तक 160 किलोग्राम के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत में इस्पात उद्योग की सफलता के पीछे लौह अयस्क और लागत सक्षम श्रमशक्ति की उपलब्धता के साथ निर्माण क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत उत्पाद, रेलवे, वाहन उद्योग से आने वाली मजबूत मांग प्रमुख कारक है। भारत विश्व का चौथा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। देश में इस्पात उत्पादक कंपनियां छह लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करती हैं।

चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। इस्पात बाजार में भारत की बढ़ती भागीदारी को कमजोर करने के लिए वह हर पैंतरे अपना रहा है। चीन के सस्ते और स्तरहीन स्टील की वजह से भारतीय कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। भारत ने चीन से खपाए जाने वाले दोयम दर्जे के स्टील को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपाय किए हैं। चीन के बाद भारत में इस्पात के सबसे बड़े आयातक दक्षिण कोरिया और जापान हैं। भारत को होने वाले कुल आयात में इन तीन देशों की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत है। अभी स्टील के आयात पर 12 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क और 7.5 प्रतिशत न्यूनतम सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार ने देश में तैयार होने वाले तथा आयातित स्टील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीआइएस मानकों को अधिसूचित किया है। इससे भारत ने इस वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में चीनी इस्पात आयात में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती कर इसे 0.2 मिलियन टन तक लाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि वियतनाम से आयात अप्रैल और मई में नगण्य हो गया है। केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन कच्चे माल पर आयात शुल्क शून्य किया गया है, जो निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होते हैं। कई कंपनियां आयात शुल्क में कमी का लाभ तो लेती हैं, लेकिन तैयार माल को निर्यात के बजाय घरेलू बाजार में बेच देती हैं। इससे भारत की इस्पात निर्यात की क्षमता कमजोर होती है।

भारत को स्टील के वैश्विक बाजार में टिकाऊ मौजूदगी दर्ज कराने के लिए घरेलू बाजार को मजबूत करने के साथ नए बाजार तलाशने होंगे। अभी इटली, बेल्जियम और संयुक्त अरब अमीरात हमारे लिए स्टील के सबसे बड़े खरीदार हैं। देश के स्टील उद्योग को मजबूती देने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय भी करने होंगे। स्टील सेक्टर की लागत का एक बड़ा हिस्सा बिजली में खर्च होता है। निश्चित अवधि के लिए बिजली की दरें निश्चित की जा सकती हैं। स्टील का 50 प्रतिशत हिस्सा लगभग सरकारी अवसंरचनाओं में खर्च होता है। ऐसे में सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर में जितना अधिक खर्च बढ़ाएगी, उसका लाभ इस्पात उद्योग को मिलेगा। इस्पात निर्माण में लौह अयस्क की सबसे अहम भूमिका होती है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की गुणवत्ता बेहतर बनाकर उच्च कोटि के इस्पात उत्पाद तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके लिए तकनीक एवं नवाचार को बढ़ाना होगा। इस्पात तैयार करने में लौह अयस्क के बाद कोकिंग कोल दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है। भारतीय इस्पात उद्योग अपनी जरूरत का 70 प्रतिशत कोकिंग कोल आयात करता है। सरकार ने विदेश पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए 2021 में मिशन कोकिंग कोल शुरू किया है। वर्तमान में कोकिंग कोल के उत्पादन का बड़ा हिस्सा झारखंड में ही सीमित है। सरकार और कोकिंग कोल ब्लाक की नीलामी कर रही है।

आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण होती है स्टील की भूमिका। फाइल

मुक्त व्यापार समझौते एक ओर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए वरदान बन रहे हैं, इससे भारतीय निर्यातकों को शुल्क रहित बड़े बाजार मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एफटीए भारत में खराब गुणवत्ता के स्टील खपाने का जरिया भी बन गया है। इसके लिए मुक्त व्यापार समझौतों में यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ वैध और मानकों पर खरे उत्पादों को ही मिले। अभी इस्पात उद्योग से जुड़े शोध एवं डाटा संकलन की व्यवस्था कमजोर है, इसे बेहतर बनाया जाना चाहिए।

****

दैनिक जागरण
सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं

डिजाइन इन इंडिया

प्रधानमंत्री ने सेमीकान इंडिया कार्यक्रम में विश्व भर के निवेशकों को भारत आने का निमंत्रण देते हुए डिजाइन इन इंडिया की जो बात कही, वह मेक इन इंडिया का विस्तार ही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उल्लेख किए बगैर यह भी कहा कि भारत आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि वे ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति की ओर संकेत कर रहे थे। इसके पहले भी वे ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों को रेखांकित करते हुए स्वदेशी का आह्वान कर चुके हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले लगभग पांच वर्षों और विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। जब स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है तो कुछ उत्साही लोग और संगठन चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाने लगते हैं। इस सबके बीच तथ्य यह है कि न तो स्वदेशी अपनाने की दिशा में अपेक्षित ढंग से आगे बढ़ा जा पा रहा है और न ही देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया के तहत जो पहल की जा रही है, वह कारगर साबित होगी। इससे इन्कार नहीं कि मेक इन इंडिया पहल ने काफी कुछ प्रभाव दिखाया है और इसका प्रमाण यह है कि आज भारत में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बन रहे हैं और वे निर्यात भी हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में जो सफलता मिलती दिख रही है, वह भी इसी पहल का परिणाम है, लेकिन यह समझना कठिन हो रहा है कि भारतीय उद्योग जगत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैसी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा है, जैसी उसकी ओर से की जानी चाहिए थी?

आखिर क्या कारण है कि भारतीय उद्योग जगत चीनी वस्तुओं पर निर्भर है? तमाम प्रयासों के बावजूद चीन से वे वस्तुएं तो आ ही रही हैं, जिनका उत्पादन भारत में आसानी से संभव नहीं, लेकिन इसके साथ ही उन वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है, जिन्हें देश में सहज ही निर्मित किया जा सकता है और जो एक समय निर्मित होती भी थीं। यह ठीक नहीं कि रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भी बड़े पैमाने पर चीन से आ रही हैं। सरकार को उन कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करना होगा, जिनके चलते अतिसंपन्न एवं समर्थ उद्योगपति भी शोध एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं। जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, तब तक न तो चीन की चुनौती का सामना किया जा सकता है और न ही अमेरिका के भारत विरोधी रवैये का। अच्छा यह होगा कि सरकार छोटे एवं मझोले उद्यमियों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के अपने अभियान में शामिल करे।

मंत्रियों का उत्तरदायित्व

अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में भाजपा अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रही है। ऐसा वर्ष में एक बार तो अवश्य ही किया जाना चाहिए। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हर दल चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र इसलिए जारी करता है कि वह सरकार बनने के बाद अपने घोषणा पत्र को पूरा करेगा। यह भी स्पष्ट है कि किसी भी राज्य सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और नीतियां एवं योजनाएं बनाने में राज्य स्तर पर उसका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के मंत्री की होती है। ऐसे में, मंत्रियों का उत्तरदायित्व ज्यादा होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के आगामी दिसंबर में दो साल पूरे होने जा रहे हैं। इतना समय किसी भी मंत्री के लिए उसके विभागीय कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए कम नहीं होता। ऐसे में, उनके कार्यों की समीक्षा इसलिए भी अनिवार्य हो जाती है, ताकि भाजपा अगले तीन वर्ष के अपनी इस सरकार के कार्यकाल के लिए जनहित की योजनाओं और कार्यों को गति देने के लिए रोडमैप तैयार कर सके। बेहतर यही होगा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा केवल निष्कर्ष तक सीमित न रखे, बल्कि अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों के दायित्व में परिवर्तन पर भी विचार करे। इस कार्रवाई से दूसरे मंत्री सबक लेकर बेहतर कार्य करने को बाध्य होंगे।

> मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की सार्थकता तभी है, जब अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने वालों के दायित्व में परिवर्तन किया जाए

चीन को सुधारना होगा अपना रवैया

हर्ष वी. पंत

चीन यदि भारत का भरोसा चाहता है तो उसे भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार खोलना और पाकिस्तान पर दबाव डालना होगा कि वह आतंक से बाज आए

शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री सात साल बाद चीन गए। इस दौरान मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कई अन्य नेताओं के साथ उनकी वार्ता हुई। खासतौर से चिनफिंग के साथ लंबे अर्से बाद मेल-मुलाकात और पुतिन के साथ उनकी आत्मीयता खासी चर्चित रही। एक ऐसे दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां विशेषकर टैरिफ नीति दुनिया में हलचल मचा रही है, तब मोदी-चिनफिंग-पुतिन की तिकड़ी पर दुनिया भर की नजरें टिकना स्वाभाविक ही था। एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री ने भारत की प्राथमिकताओं को भी प्रमुखता से सामने रखा। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम आतंकी हमले की एससीओ द्वारा निंदा करना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही। यह रुख जून में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के उलट रहा, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर दोहरा रवैया दिखाया गया था। नई दिल्ली के लिए यह परिणाम न केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एससीओ चार्टर के केंद्रीय मिशन को फिर से स्थापित करता है, बल्कि सदस्य देशों और यूरेशिया के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवाद की ओर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित करता है। शिखर सम्मेलन से पहले और बाद में प्रधानमंत्री ने म्यांमार, मालदीव, मध्य एशिया, बेलारूस, रूस, आर्मेनिया और मिस्र के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं, ताकि कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके।

कई मोर्चों पर प्रगति के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि एससीओ आंतरिक विरोधाभासों से भरा हुआ है। कई सदस्य इस मंच का उपयोग अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति और भू-राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, जिससे परस्पर विश्वास का अभाव और मतभेद उत्पन्न होते हैं। इसका ही परिणाम है कि यह मंच आतंकवाद, कनेक्टिविटी की कमी और अफगानिस्तान की स्थिति जैसे प्रमुख क्षेत्रीय संकटों के प्रभावी ढंग से समाधान में असफल रहा है। चीन की भूमिका भी समस्याओं से भरी है। भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे पाकिस्तान का चीन हरसंभव तरीके से बचाव करता आया है। पाकिस्तान के 80 प्रतिशत से अधिक रक्षा उपकरण अब चीन से आने लगे हैं। आपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तान को सहायता पहुंचाई। बीजिंग के संकीर्ण रणनीतिक हितों ने अफ-पाक क्षेत्र को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। इससे एससीओ कमजोर पड़ता है।

अवधेश राजपूत

वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होने के बाद से भारत ने इस संगठन को कनेक्टिविटी और ऐसे सहयोगात्मक प्रयासों की ओर मोड़ने का प्रयास किया है, जो संप्रभुता का सम्मान करते हों। नई दिल्ली की प्राथमिकताएं साझा संस्कृति और साझा भविष्य पर केंद्रित रही हैं। उसने भरोसेमंद, लचीली और विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं पर जोर दिया है। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता के साथ ही सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी अनिवार्य है। नई दिल्ली ने एससीओ मंच का उपयोग अपने भू-राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्यों को मध्य एशिया में आगे बढ़ाने और चीन के आक्रामक प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी किया है। भारत की सक्रियता के चलते ही मध्य एशियाई देशों ने 2018 में उसे अस्ताना समझौते में शामिल किया और चाबहार पोर्ट एवं अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को लेकर पूर्वी मार्ग में रुचि दिखाई। इसी वर्ष जून में भारत और मध्य एशिया ने नई दिल्ली में चौथे भारत-मध्य एशिया संवाद के दौरान रेयर अर्थ और खनिजों को लेकर बात आगे बढ़ाई। यह कदम बीजिंग द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिए रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया। मध्य एशिया को बीजिंग के प्रभुत्व के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वहां रेयर अर्थ तत्वों के समृद्ध भंडार हैं। अकेले कजाकिस्तान में ही बहुत बड़ी तादाद में रेयर अर्थ तत्व हैं, जिनका मूल्य 46 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर से अधिक बताया जा रहा है।

एससीओ ने भारत और चीन को सीधे संवाद का एक मंच भी प्रदान किया और दोनों देशों ने मतभेदों के बावजूद द्विपक्षीय मुद्दों पर समाधान तलाशने की इच्छा भी जताई। इन मुद्दों में सीमा निर्धारण और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ के तहत गुलाम जम्मू-कश्मीर में चीनी निवेश जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वैश्विक दक्षिण द्वारा संचालित ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के माध्यम बने हैं। युद्धों, संघर्षों, टैरिफ और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों वाले इस दौर में बीजिंग और नई दिल्ली को दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ सहयोग करना चाहिए। उनकी बढ़ती भूमिका और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक भी है। इससे बहुपक्षीयता और बहुध्रुवीय विश्व बनाने की इनकी संकल्पना को भी बल मिलेगा। हालांकि संबंधों की सही दशा-दिशा के लिए चीन को भी यह तय करना होगा कि वह भारत के साथ संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएगा। इसके लिए उसे भारतीय वस्तुओं और आइटी सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना और पाकिस्तान पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दबाव डालना होगा।

जब युद्ध, टैरिफ और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रही हैं, तब भारत की एससीओ में वापसी बहुपक्षीयता के प्रति उसके महत्व को दर्शाती है। मोदी की भागीदारी को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक व्यावहारिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के लिए एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच अपनी आवाज उठाने, सुरक्षा हितों की पूर्ति और यूरेशिया में अपनी आर्थिक पैठ को विस्तार देने वाले माध्यम की भूमिका निभाते हैं। हाल के सम्मेलन से जो सकारात्मक संकेत मिले हैं, उन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए चीन को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कथनी एवं करनी में कोई भेद नहीं। तभी एससीओ प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर बहुध्रुवीय स्थिरता का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सकता है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

गरीबों को सशक्त बनाने वाली योजना

रमेश कुमार दुबे

जनधन योजना वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई है

इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 67 साल बाद भी देश के आधे परिवारों के लिए बैंकिंग तक पहुंच दूर का सपना था। वित्तीय सुरक्षा के अभाव में गरीबों के सपने कभी साकार नहीं हो पाते थे। तब भले ही बैंकों को गरीबों का हितैषी कहा जाता हो, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर उनका ढांचा गरीबों के अनुकूल नहीं रहा। देश में गरीबी की व्यापकता एवं उद्यमशीलता के माहौल में कमी का एक बड़ा कारण बैंकों तक गरीबों की पहुंच न होना रहा। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि अब बैंकों की चौखट तक गरीबों की पहुंच बढ़ेगी, पर समय के साथ यह उम्मीद धूमिल पड़ती गई। 2013 में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वित्तीय समावेशन पर नचिकेता मोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए अधिक व्यापक वित्तीय ढांचे की सिफारिश करते हुए कहा कि चूंकि गरीब बचत करते हैं, इसलिए उनके लिए एक ऐसी सुरक्षित एवं ब्याज कमाने वाली औपचारिक योजना की जरूरत है, जिस तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

आजादी के 67 वर्षों तक जहां आम आदमी को आसानी से बचत खाता तक नसीब नहीं हुआ, वहीं भ्रष्ट नेताओं-नौकरशाहों-ठेकेदारों के बैंक खाते विदेशी बैंकों में खुलते गए। बैंकों की सीमित पहुंच का दुष्परिणाम यह हुआ कि हर स्तर पर बिचौलियों-भ्रष्टाचारियों की भरमार हो गई। इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहकर स्वीकार भी किया था कि विकास के लिए दिल्ली से चला एक रुपया गरीबों तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा ही रह जाता है। स्पष्ट है शेष 85 पैसा बिचौलियों-भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने 'सबका साथ-सबका विकास' के लिए आम जनता को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया था, उसी के तहत थी जनधन योजना। 'हर घर का पासबुक' जैसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से पीएम जनधन योजना शुरू करने का एलान किया। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई और इस दिन बैंकों ने गरीबों का खाता खोलने के लिए देश भर में 60,000 शिविर लगाए। पहले ही दिन देश भर में डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए। इस कामयाबी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त को 'वित्तीय स्वतंत्रता दिवस' करार दिया।

वित्तीय क्रांति का आधार बनी जनधन योजना। फाइल

आम तौर पर गरीबों की हितैषी कही जाने वाली योजनाएं शुरू तो धूम-धड़ाके के साथ होती हैं, लेकिन बाद में वे भ्रष्ट तत्वों के जीने-खाने का जरिया बन जाती हैं, परंतु जनधन योजना के साथ ऐसा नहीं हुआ। मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते 2014 के पांच महीनों में दस करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, जो एक विश्व रिकार्ड है। गरीबों को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने की यह गति अभी भी जारी है। पिछले 11 वर्षों में 56.16 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें से 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए और 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इस प्रकार जनधन योजना वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। इन खातों में कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। इन खातों से जुड़े 38 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इससे डिजिटल लेनदेन आसान हुआ है। एक तरह से इस योजना ने नकदी रहित भुगतान के लिए नींव का काम किया।

पीएम जनधन योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हर स्तर पर भ्रष्टाचारियों-बिचौलियों का उन्मूलन हो गया। आज केंद्र सरकार की 327 सरकारी योजनाओं का पैसा प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जा रहा है। यदि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों की योजनाओं को भी मिला लें तो कुल 1,200 योजनाओं में से 1,100 योजनाएं डीबीटी के दायरे में आ चुकी हैं। डीबीटी की सफलता में जेएएम यानी जनधन, आधार और मोबाइल का महत्वपूर्ण स्थान है। जेएएम के कारण ही भारत में डिजिटल पेमेंट का आंदोलन संभव हो पाया। आज भारत में विश्व का 40 प्रतिशत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इसीलिए भारत की डिजिटल क्रांति दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के एक अध्ययन के अनुसार भारत की डीबीटी प्रणाली ने कल्याणकारी कार्यक्रमों में रिसाव को रोककर देश को 3.48 लाख करोड़ रुपये बचाने में मदद की है। रिपोर्ट में भी यह भी पाया गया कि डीबीटी के बाद से सब्सिडी आवंटन कुल सरकारी व्यय के 16 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत रह गया है, जो सार्वजनिक व्यय की दक्षता में एक बड़ा सुधार है।

जनधन योजना को मिली अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इस योजना के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह रेखांकित किया कि जब अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। उन्होंने इसे उचित ही भारत की वित्तीय क्रांति की नींव बताया।

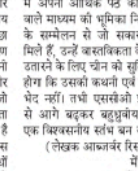

(लेखक निर्यात संवर्द्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

समय की महत्ता

हर मनुष्य के लिए वर्ष, माह, सप्ताह का समय और दिन के घंटे निर्धारित हैं। इसी अवधि में हर कोई जीवन जीता है। संयोगवश कोई सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो कोई विफलता के दलदल में फंसा रह जाता है। इसकी पड़ताल करें तो यही पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने वाले ने योजनाबद्ध ढंग से समय का सदुपयोग किया। आज जो काम करना है, उसे कल पर नहीं टालकर कार्य को समय पर पूर्ण कर लिया। जबकि विफल होने में आलस्य सबसे बड़ा दोषी होता है। इसका सार यही है कि हर विफल व्यक्ति ने समय के महत्व को नहीं समझा। आज कोई काम करना है तो उसे टालता रहा। इस क्रम में जब काम का अंबार लग जाता है, तब समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से की जाए? जब काम की दिशा में कदम बढ़ाए तो पता चलता है कि बहुत विलंब हो चुका है। उसका समय निकल गया है। ऐसी स्थिति में कल को कोसने के सिवाय और कोई उपाय नहीं रहता। कल को कोसने का मतलब खुद को कोसना, क्योंकि समय से कदम नहीं उठाने के लिए समय नहीं, बल्कि खुद वही व्यक्ति दोषी है।

महाभारत में अर्जुन भी शस्त्र उठाने से हिचकने लगे थे। अर्जुन की इस मनःस्थिति को देखकर ही भगवान श्रीकृष्ण को उपदेश देना पड़ा। श्रीकृष्ण द्वारा गीता का उपदेश सिर्फ दो पक्षों के बीच किसी युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक जगत को सजग और चैतन्य करने के लिए है। शस्त्र का अर्थ भी कर्म होता है। मनुष्य की भुजाएं, मन और मस्तिष्क सब शस्त्र हैं। याद रहे कि जो बीत गया, कितना भी अनुकूल वातावरण रहा हो, वह लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आज फिर वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। विश्व बहुत विराट है। समय शत्रु है तो मित्र भी है। समय का सम्मान करना जिसने सीख लिया, वह जिंदगी की दौड़ में पीछे रह ही नहीं सकता।

सलिल पाण्डेय

रेल की पटरियों के बीच सौर ऊर्जा की संभावनाएं

सुधीर कुमार

बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना में पहली बार रेल की पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है

भारतीय रेलवे ने रेल की पटरियों के बीच सौर ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने में कामयाबी हासिल की है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना में पहली बार रेल की पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। पायलट-प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 70 मीटर रेलवे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं, जिससे 18 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। इस पहल ने साबित किया है कि रेल की पटरियां रेल-परिवहन को गति देने के साथ सतत ऊर्जा का आधार भी बन सकती हैं।

स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया के किसी भी देश ने अब तक रेल की पटरियों के बीच सौर पैनल लगाने के प्रयोग को धरातल पर नहीं उतारा है। स्विट्जरलैंड ने इसी वर्ष अप्रैल महीने में कैंटन न्यूचैटेल के बट्स स्टेशन में परीक्षण के तौर पर 100 मीटर रेलवे ट्रैक पर 48 सौर पैनल लगाए हैं, जिससे वहां कुल 18 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव हुआ है। वहां इस परीक्षण को लगभग तीन वर्ष तक चलाया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे स्विट्जरलैंड में लागू करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता के बल पर इस दिशा में आगे बढ़कर वैश्विक नेतृत्व का परिचय दिया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भारतीय रेलवे का सराहनीय योगदान रहा है। रेलवे अपनी ऊर्जा आवश्यकता को परंपरागत ऊर्जा के बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है। रेल की पटरियों के बीच सौर उत्पादन की संभावनाएं तलाश कर भारत ने न सिर्फ अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अमिट छाप भी छोड़ी है।

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार, 2020 तक रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। इसमें ब्राड गेज (1676 मिमी) मार्ग का हिस्सा 94 प्रतिशत तक है। इतनी लंबी पटरियों पर यदि बड़े पैमाने पर सौर पैनल लगाए जाएं तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि संभव है। रेल की पटरियों पर सौर पैनल बिछाकर उसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए करना एक क्रांतिकारी विचार है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाता है, जिससे सौर फार्मों के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। साथ ही इससे ट्रेन परिचालन को बाधित किए बिना इसके समानांतर ऊर्जा उत्पादन को संभव बनाया जा रहा है। वहीं पटरियों की सफाई और रखरखाव के दौरान सौर पैनल को आसानी से हटाने की विशेषता इसे और भी खास बनाती है। बहरहाल देशभर में इसका प्रयोग अक्षय ऊर्जा के भंडार को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

चुनौतियों पर भी दिया जाए ध्यान

'सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की क्रांति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अश्विनी वैष्णव ने भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर आत्मनिर्भरता और निवेश की अपार संभावनाओं पर बल दिया है। यह विचार निश्चय ही प्रेरक है कि 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रम भारत को इलेक्ट्रानिक उत्पादन का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं। इससे रोजगार, पूंजी प्रवाह और तकनीकी विस्तार की नई राहें खुल सकती हैं। हालांकि, इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उच्चस्तरीय मानव संसाधन की कमी आज सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि चिप डिजाइन, नैनो-इंजीनियरिंग और वेफर फैब्रिकेशन जैसे जटिल क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता अभी अपर्याप्त है। इसके साथ ही कच्चे माल और उपकरणों के लिए बाहरी निर्भरता इतनी अधिक है कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला की किसी भी बाधा से पूरा ढांचा कमजोर हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय संतुलन भी बड़ी चुनौती है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पानी और ऊर्जा की अत्यधिक खपत करता है और यदि इसके लिए स्थायी वैकल्पिक रणनीति नहीं बनी तो विकास का यह माडल समाज पर अतिरिक्त बोझ बन सकता है। यह विडंबना है कि जिस क्रांति की कल्पना आत्मनिर्भरता के नाम पर की जा रही है, वही यदि असंतुलन पैदा करे तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव हानिकारक होगा। भारत के पास नीतिगत स्थिरता और विशाल उपभोक्ता बाजार जैसी ठोस ताकतें मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी पिछड़ेपन और संसाधन-प्रबंधन की चुनौतियों से पार पाना अनिवार्य होगा। यदि देश केवल विनिर्माण केंद्र तक सीमित न रहकर नवाचार और अनुसंधान का भी वैश्विक नेतृत्वकारी केंद्र बने तब ही यह क्रांति टिकाऊ और सार्थक सिद्ध होगी।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

अनवरत परीक्षाओं का जाल

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए टीईटी अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा छोड़नी पड़ेगी या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनी होगी। यह स्थिति एक गंभीर सवाल खड़ा करती है-क्या वास्तव में इन अलग-अलग परीक्षाओं से शिक्षक की गुणवत्ता तय होती है? सच तो यह है कि बीएड और बीटीसी जैसे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर पढ़ाई हो, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाए और नियमित मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी हो, तो अलग से टीईटी या सुपर टीईटी जैसी परीक्षाओं की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरी ओर, इन परीक्षाओं के नाम पर मोटी फीस लेकर बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को वर्षों तक तैयारी और परीक्षा की दौड़ में उलझाए रखना शिक्षा सुधार का उपाय नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक और मानसिक थकान का कारण बन गया है। आवश्यकता इस बात की है कि भर्ती प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। शिक्षक जिस तरह पढ़ाते हैं और छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर निगरानी और मूल्यांकन ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। शिक्षा सुधार का सही रास्ता शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उनकी कार्यकुशलता पर ध्यान देना है, न कि अनवरत परीक्षाओं के जाल में उन्हें फंसाना।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

राहुल का हाइड्रोजन बम

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया "हाइड्रोजन बम" वाला बयान अत्यंत ही गैर-गंभीर और बचकाना प्रतीत होता है। इस प्रकार की भाषा और उपमाओं का प्रयोग न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को आहत करता है, बल्कि देश की राजनीतिक संस्कृति को भी कमजोर करता है। पूर्व में उन्होंने "एटम बम" जैसी टिप्पणी की थी, जो पूरी तरह फुस्स सिद्ध हुई। अब "हाइड्रोजन बम" की धमकी देकर वे जनता को भ्रमित करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह समझ से परे है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका वर्तमान नेतृत्व इस तरह के हास्यास्पद और गैर-जिम्मेदार बयानों से अपनी साख को निरंतर गिराता जा रहा है।

sureshgoyal8@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

चिंतन

खुद अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहा विपक्ष

बीते एक दशक से जो हर चुनाव के दौरान होता है, ठीक वैसे ही हुआ। विपक्ष ने बैठे बिठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के प्रति अपशब्द कहकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। वोटर अधिकार यात्रा के दौरन बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को एक शख्स ने मां की गाली दे दी थी। हालांकि, उस समय मंच पर न राहुल गांधी थे और न ही तेजस्वी यादव, लेकिन मंच सजा था राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिनों तक बिहार के कोने-कोने में रैलियां कीं। उनकी रणनीति जातिगत समीकरणों को साधना, युवाओं को रोजगार का सपना दिखाना और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना था। दोनों बिहार के मतदाता सूची से 65 लाख वोटरों के नाम कटने का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मंगलवार को गाली को बिहार ही नहीं देश की सभी मां और बहनों के साथ जोड़कर पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था। उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए। हालांकि यह पहली बार यह नहीं है जब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज भावुक अंदाज में बिहार की महिलाओं के सामने यह बात कही, उससे एक बात साफ है कि जल्द होने वाले बिहार चुनाव में यह मुद्दा बनेगा। जब-जब विपक्ष ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे, यह विपक्ष पर ही भारी पड़ गया। इससे पहले भी मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, चायवाला जैसे अनेक उदाहरण हैं। गुजरात में साल 2002 के दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2007 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं। मोदी ने इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ हथियार में बदल दिया। यह बयान आज भी कांग्रेस के लिए नासूर के समान है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कांग्रेस का इस बयान से पीछा नहीं छूटा। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। वह गुजरात से दिल्ली आ चुके थे। इस चुनाव के दौरान ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चायवाला कहा। नरेंद्र मोदी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और हर चुनावी मंच से अपने आप को चायवाला कहकर संबोधित किया। जनता पर इसका सीधा असर भी हुआ। कांग्रेस की करारी हार हुई। हालांकि आखिरी बार ऐसा नहीं था। मणिशंकर के ऐसे बयान बाद में भी सामने आते रहे, वो एक बार पीएम मोदी को नीच भी कह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। पीएम मोदी ने इस नारे का भी इस्तेमाल अपने पक्ष में किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया। कुछ ही समय में उस वक्त मैं भी चौकीदार ट्रेंड करने लगा। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो सबको चौंका दिया। चुनाव परिणाम ने बता दिया कि जनता इस नारे से बहुत नाराज हुई। अब बिहार विस चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहकर राजग को मुद्दा थमा दिया है। जल्द ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। विपक्ष को यह मुद्दा कितना भारी पड़ता है, इसका असली पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। हालांकि एक बात तो तय हो गई है कि चुनाव में यह मुद्दा जरूर बनने वाला है। भाजपा इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली।

मुद्दा

अली खान

तंबाकू सेवन की व्यापकता को रोकने की चुनौती

हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर रोधक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन ने देश में तंबाकू सेवन की भयावह स्थिति को उजागर कर दिया है। अध्ययन में यह सामने आया है कि देशभर के 100 जिलों में तंबाकू का अत्यधिक सेवन हो रहा है, जिनमें से अधिकतर जिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें से 68 जिलों में धुआं रहित तंबाकू का सेवन व्यापक रूप से प्रचलित है। धुआं रहित तंबाकू से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से है जिन्हें जलाकर धुआं नहीं पैदा किया जाता, बल्कि उन्हें सीधे चबाया, चूसा या मुंह में रखा जाता है। इसमें खैनी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू मिश्रित सुपारी जैसे उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद जितने सुलभ और सस्ते हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। अध्ययन के मुताबिक, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 21.4 प्रतिशत लोग धुआं रहित तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। पुरुषों में यह प्रतिशत लगभग 29.6 और महिलाओं में 12.8 है। यह आंकड़ा इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि तंबाकू की लत समाज में कितनी गहराई तक पैठ बना चुकी है। खासतौर पर गरीब और अशिक्षित वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों और श्रमिक तबके में इसकी खपत अत्यधिक है। यह वर्ग न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर होता है, बल्कि उन्हें तंबाकू सेवन से जुड़ी बीमारियों का इलाज कराने में भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें मध्य प्रदेश के 15 जिले, उत्तर प्रदेश और बिहार के 11-11 जिले तथा ओडिशा के भी कई जिले इस सूची में शामिल हैं। इन जिलों का चयन यह दर्शाता है कि तंबाकू सेवन केवल किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या व्यापक रूप से फैली हुई है। हालांकि, यह बात भी सामने आती है कि जिन जिलों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ापन ज्यादा है, वहां तंबाकू का सेवन अधिक होता है। लोग तंबाकू को सस्ता और आसानी से उपलब्ध नशा मानते हैं, जिससे वे अस्थायी रूप से तनाव और थकान से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। परंतु यह राहत बहुत ही क्षणिक होती है और इसके दीर्घकालिक परिणाम बेहद घातक साबित होते हैं। यद्यपि पुरुष उपभोक्ताओं की संख्या महिलाओं से दोगुनी से भी अधिक है, लेकिन महिलाओं में भी यह आदत चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण समाज में विशेषकर महिलाएं घरेलू काम के दौरान खैनी या सुपारी के साथ तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं। कुछ जगहों पर इसे परंपरा या आदत के रूप में भी देखा जाता है। तम्बाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति केवल स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती बल्कि सामाजिक और आर्थिक बोझ भी बढ़ाती है। तंबाकू के कारण उत्पन्न बीमारियों के इलाज पर सरकार और आम जनता दोनों को भारी खर्च उठाना पड़ता है। गरीब तबके को इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार इलाज के अभाव में लोग असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी का भी मानना है कि तंबाकू महामारी दुनिया के सामने आने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इससे हर साल 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती हैं। इनमें से 70 लाख से अधिक लोगों की मौतें सीधे तंबाकू के उपयोग का नतीजा हैं, लेकिन लगभग 13 लाख लोगों की मौत सीधे तौर पर धूम्रपान करने के बजाय अन्य लोगों द्वारा धूम्रपान करने से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से होती है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, धूम्रपान अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह और पुरानी सांस की बीमारियों का कारण बनता है। ऐसे में तंबाकू का इस्तेमाल स्वास्थ्य संकट को बढ़ा रहा है। हालांकि सरकार ने तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। फिर भी इसका प्रचलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा, तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जाए। सबसे पहले शिक्षा और जागरूकता पर जोर देना होगा। दरअसल, तंबाकू से होने वाला नुकसान इतना व्यापक है कि इसे केवल व्यक्तिगत आदत कहकर टाला नहीं जा सकता। यह समस्या सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो तंबाकू के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तंबाकू सेवन पर अंकुश लगाना केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की एक अनिवार्य शर्त है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं शिक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आत्मनिर्भरता

डॉ. अश्विनी महाजन

स्वदेशी के साथ आगे बढ़े भारत

> यह सही है कि भारत चीन की उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। बीजिंग के साथ हमारा व्यापार घाटा हर साल 100 अरब डॉलर को पार कर जाता है। चीनी बंदरगाहों से आने वाला हर कंटेनर जहाज चीन पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। इसी संदर्भ में, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा को देखा जाना चाहिए। वे भारत का संदेश लेकर गए, हमारा स्वदेशी सीमित नहीं है, यह व्यापक है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, हमारे लोगों को सशक्त बनाता है और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था में योगदान देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वदेशी को अपनाने का समय आ गया है। जो 'मेक इन इंडिया' से शुरू हुआ, आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में विकसित हुआ, अब स्वदेशी के गहन और समग्र विचार की ओर बढ़ रहा है। यह केवल एक नारा नहीं है। यह एक सभ्यतागत अनिवार्यता है। यह सही है कि भारत चीन की उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। बीजिंग के साथ हमारा व्यापार घाटा हर साल 100 अरब डॉलर को पार कर जाता है।

वर्तमान में, हमारे दो-तिहाई से ज्यादा सौर मॉड्यूल, हमारी 70 प्रतिशत से ज्यादा दवा सामग्री और अरबों डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सीमा पार से आते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये कमजोरियां हैं। चीनी बंदरगाहों से आने वाला हर कंटेनर जहाज चीन पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। इसी संदर्भ में, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा को देखा जाना चाहिए। उनकी वहां उपस्थिति कोई रियायत नहीं; एक बयान है। भारत बातचीत करेगा, लेकिन स्पष्टता और विश्वास की स्थिति से। बातचीत का मतलब निर्भरता नहीं है। बातचीत का मतलब राष्ट्रीय हितों को कमजोर करना नहीं है। संदेश सीधा है: भारत जहां तक संभव हो, सहयोग चाहता है, लेकिन अपनी आर्थिक संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। हाल के अध्ययन, जिनमें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझ परिषद (सीआइयू) द्वारा तैयार भारत के भू-आर्थिक ढांचे में चीन अध्ययन के लिए रणनीतिक अनिवार्यता भी शामिल है, इस खतरे को रेखांकित करते हैं। ये अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे चीन का राज्य-प्रधान मॉडल- औद्योगिक अति-क्षमता, डंपिंग, सब्सिडी और वित्तीय इंजीनियरिंग-बाजारों को विकृत करता है और भारत के विनिर्माण आधार के लिए खतरा पैदा करता है। ये अध्ययन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा में चीनी इनपुट पर हमारी खतरनाक निर्भरता की ओर भी इशारा करते हैं, और चेतावनी देते हैं कि संकट के समय ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं तक पहुंच को आसानी से हथियार बनाया जा सकता है। देश की करीब 50 स्वदेशी कंपनियां आज भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे भारत की मिसाइल प्रणाली ने चीन की वायु-रक्षा प्रणाली को परास्त कर डाला था। ये जानकारियां एक बात बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि भारत प्रतिक्रियात्मक रुख नहीं अपना सकता, उसे स्वदेशी पर आधारित एक सक्रिय सिद्धांत अपनाना होगा। चीन के दृष्टिकोण के विपरीत, स्वदेशी साम्राज्यवादी नहीं है। यह ऋण या जबरदस्ती के माध्यम से दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। हमारा स्वदेशी वसुधैव कुटुम्बकम-दुनिया एक परिवार है-के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा दृष्टिकोण देश में आत्मनिर्भरता और विदेश में निष्पक्ष, सहयोगात्मक साझेदारी का है। यह भारत में न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करने के बारे में है, जो लचीलेपन और सम्मान को मजबूत करता है। वैश्विक स्तर पर, स्थिति बदल रही है। टैरिफ का हथियारीकरण-जो ट्रम्प की पहली पारी में स्पष्ट हुआ और अब वैश्विक व्यापार का एक अभिन्न अंग बन गया है- ने

सरकारों और व्यवसायों को अपनी आपूर्ति शृंखलाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में, कंपनियां चीन के विकल्प तलाश रही हैं। जहां कई लोग इसे 'चीन+1' कहते हैं, वहीं भारत को एक बड़े विचार को आगे बढ़ाना होगा : भारत+अनेक। भारत के पास विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र बनने के लिए पर्याप्त पैमाना, प्रतिभा और सभ्यतागत लोकाचार है। हमें घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। सरकार ने पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, और व्यापार धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों में संशोधन। ये उपाय, आसियान मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के भीतर भारत की पुनर्वार्ता और यूरोपीय संघ के साथ नए जुड़ाव के साथ, व्यापार नीति को राष्ट्रीय हित के अनुरूप बनाने की इच्छा को दर्शाते हैं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सीआईईयू अध्ययन सही ही सिफ़ारिश करता है कि भारत को अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश को दोगुना करके सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करना चाहिए, यह एक आवश्यक कदम है। यदि हमें सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और अगली पीढ़ी की तकनीकों में नवाचार की खाई को पाटना है। यह सरकार के भीतर एक समर्पित चीन आर्थिक जोखिम निगरानी इकाई- जो जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, चीनी प्रथाओं पर नजर रखने और सक्रिय नीति निर्धारण को सूचित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र- की भी मांग करता है। दोनों ही जरूरी और आवश्यक हैं। साथ ही, स्वदेशी सिद्धांत-आधारित साझेदारी का आह्वान करता है। चाहे क्वाड, आसियान, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के माध्यम से, भारत को एक वास्तविक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना चाहिए। इसी तरह भारत '+1' की परिधि से 'अनेक' के केंद्र की ओर बढ़ सकता है।

जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर रहे थे, तो वे भारत के वार्ता संबंधी दायित्व से कहीं अधिक लेकर गए। वे भारत का संदेश लेकर गए कि हमारा स्वदेशी सीमित नहीं है, यह व्यापक है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, हमारे लोगों को सशक्त बनाता है और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था में योगदान देता है। ऐसे दौर में जब व्यापार हथियार बन गया है और आपूर्ति शृंखलाएं युद्धक्षेत्र बन गई हैं, भारत का रुख दृढ़ होना चाहिए। हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर। दुनिया को दूसरे चीन की जरूरत नहीं है। दुनिया को भारत की जरूरत है, एक ऐसे भारत की जो स्वदेशी में निहित हो और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मार्ग पर चलता हो।

(लेखक पूर्व प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

जब मन हो अशांत, करें अपने इष्टदेव का ध्यान

संकलित

दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

लक्ष्मी जी कहां निवास करतीं हैं

संकलित

प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछा- दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोले- देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं-देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोले- देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूं। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूं। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूं। इन्द्र बोले- देवी! आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इन्द्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे।

अंतर्मन

आज की पाती

देवस्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित न करे

सरकार हमारे देवस्थलों को पर्यटन के नाम पर विकसित करने के बजाय, केवल पर्यटन स्थलों को इस तर्ज पर विकसित करे। देवस्थलों व लोगों की आस्था से जुड़ी इन जगहों से छेड़छाड़ नहीं की जाए। ये स्थान लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, जो लाखों सालों से हम सबकी रक्षा करते आए हैं। हमारे देवस्थान कोई पर्यटक स्थल नहीं हैं, बल्कि लोग यहां अपने व अपने स्वजनों की कुशलता के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यहां पहुंचने के लिए हमें सड़कें नहीं चाहिए, होमस्टे नहीं चाहिए, होटल नहीं चाहिए, रोपवे नहीं चाहिए, पर्यटक नहीं चाहिए, बल्कि शांति चाहिए, श्रद्धालु चाहिए, आस्था चाहिए और देवी-देवताओं की कृपा चाहिए।

- मिलिंद जोशी, दुर्ग

ट्रेंड

मां का दुख-दर्द

मेरी मां अब शरीर इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से भी कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी जिस प्रकार उसे भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया, उनका दुख-दर्द मुझे बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के आंसुओं में साफ नजर आया।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पौधरोपण का संकल्प

प्रतिदिन पौधरोपण का संकल्प मां समान प्रकृति की सेवा का अभियान है। आज भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण कर प्रकृति सेवा के अभियान को आगे बढ़ाया। आप भी पौधरोपण अवश्य करें।

-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री

सहायता राशि भेजी

पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बारिश व बाढ़ से उत्पन्न हालात बेहद दुखद हैं। इस संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए 5-5 करोड़ की सहायता राशि भेजी गई है।

-नायब सिंह सैनी, सीएम, हरियाणा

पंजाब की मदद करें

पंजाब हमेशा देश के सामने आए किसी भी संकट का डटकर सामना करता रहा है लेकिन आज राज्य खुद संकट में है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस कठिन समय में पंजाब के लोगों की हर संभव मदद करें।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

अमेरिका में श्रमिक दिवस पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन

अमेरिका के कई शहरों में श्रमिक दिवस पर लोगों ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का सड़कों पर उतरकर विरोध किया और श्रमिकों को उचित वेतन दिए जाने की मांग की। शिकागो और न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शनों का आयोजन 'वन फेयर वेज' नामक संगठन ने किया। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य अमेरिका में श्रमिकों की परेशानियों की ओर ध्यान खींचना था, जहां न्यूनतम संघीय मेहनताना 7.25 डॉलर प्रति घंटा है। राष्ट्रपति ट्रंप के न्यूयॉर्क स्थित पूर्व आवास के बाहर ''ट्रंप को अब जाना चाहिए' के नारे गूंजे। वहीं, शिकागो में एक अन्य 'ट्रंप टॉवर' के बाहर प्रदर्शनकारियों ने 'नेशनल गार्ड नहीं चाहिए' और 'उसे जेल में डालो' के नारे लगाए।

वॉशिंगटन डी सी और सैन फ्रांसिस्को में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। न्यूयॉर्क में लोग 'ट्रंप टॉवर' के बाहर एकत्रित हुए जो वर्षों से राष्ट्रपति का निवास नहीं होने के बावजूद उनके धन-वैभव का प्रतीक और प्रदर्शनों का केंद्र बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लहराए जिन पर कथित 'फासीवादी शासन' को खत्म करने की मांग लिखी थी। वॉशिंगटन में भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

ऑफ बीट

सूर्य हमारे अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है

आज इस बात के बहुत ज्यादा सबूत नहीं हैं कि प्राचीन लोग मानते थे कि सूरज की रोशनी ही बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके बजाय, इस बात के ज्यादा सबूत हैं कि वे ठीक होने के लिए सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करते थे। एबर्स पेपीरस ईसा पूर्व 1500 साल के आसपास का प्राचीन मिस्र का चिकित्सा 'स्क्रॉल' है। इसमें ''नसों को लचीला बनाने'' के लिए मरहम बनाने की विधि दी गई है। यह मरहम शराब, प्याज, कालिख, फल और पेड़ के अर्क लोबान और लोहबान से बनाया गया था। इसे लगाने के बाद, व्यक्ति को ''सूर्य के प्रकाश में रखा जाता था।'' उदाहरण के लिए, खांसी के इलाज के लिए अन्य नुस्खों में विभिन्न सामग्री को एक बर्तन में डालकर धूप में रखना शामिल था। यही तकनीक चिकित्सा लेखन में भी है जिसका श्रेय यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है जिनका काल लगभग 450-380 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 150 ई. में आधुनिक तुर्की में सक्रिय रहे चिकित्सक एरेटियस ने लिखा था कि सूर्य का प्रकाश सुस्ती सहित कई बीमारियों को ठीक कर सकता था। इसमें वह बीमारी भी है जिसे हम आज अवसाद के रूप में पहचानते हैं। सुस्ती मिटाने का अर्थ है प्रकाश में लेटना, सूर्य की किरणों के संपर्क में आना; तथा अपेक्षाकृत गर्म स्थान में रहना।

मोदी-शी मुलाकात

बढ़ती निकटता

भारत और चीन हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहे हैं। 2020 के सीमा संघर्षों के बाद, दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ मजबूत रुख अख्तियार कर लिया था, और भारत अमेरिका की ओर झुक गया था क्योंकि चीन, अमेरिका के प्रति भारत के बढ़ते लगाव पर नाराज था। अब स्थिति बदल गई है - भारत चीन के करीब जा रहा है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति की नाराजगी और उनका प्रशासन भारत की नई विदेश नीति को बदनाम करने पर तुला हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि भारत को चीन और रूस की ओर धकेलने के लिए ट्रंप ही जिम्मेदार हैं। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन पहुंचे, तो वह सिर्फ एक नियमित कूटनीतिक मुलाकात से कहीं बढ़कर था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल - खासकर ट्रंप प्रशासन के टैरिफ हमलों से - ने भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को नया रूप दिया है। इससे पहले, 2020 के सीमा संघर्षों ने एक लंबी छाया डाली थी, और बीजिंग द्वारा पाकिस्तान की सेना को लगातार समर्थन देने से दिल्ली में दीर्घकालिक सहयोग की व्यवहार्यता पर संदेह पैदा हो गया था।

लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। मोदी के लिए, अमेरिकी मांगों के आगे झुकने का मतलब मॉस्को में एक भरोसेमंद सहयोगी को छोड़ना और घर में अपनी मजबूत छवि को कमजोर करना होता। इसके बजाय, उन्होंने अपनी साझेदारियों में विविधता लाकर खुद को स्थापित करने का विकल्प चुना है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत के निकटतम पड़ोसी चीन से बड़ा कोई साझेदार नजर नहीं आता। तियानजिन में मोदी-शी की बैठक ने इस व्यावहारिकता

को प्रतिबिंबित किया। माहौल में एक स्पष्ट बदलाव देखा जा सकता है: सीधी उड़ानों की बहाली, वीजा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, और कुछ अन्य सद्भावनापूर्ण संकेत। ये मामूली लेकिन प्रतीकात्मक कदम हैं, जो संबंधों को सुधारने के इरादे का संकेत देते हैं। मोदी के लिए, यह यात्रा उन संबंधों को फिर से स्थापित करने का एक अवसर है, जिनमें उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से बड़े उत्साह के साथ निवेश किया था। 2014 और 2018 के बीच, उन्होंने पांच बार चीन का दौरा किया। 2020 के खूनी सीमा संघर्षों ने उस गति को पटरी से उतार दिया, जिसने दोनों पक्षों को चिंतित कर दिया।

एससीओ मंच अब सावधानीपूर्वक फिर से जुड़ने का मंच प्रदान करता है। शी जिनपिंग के लिए भी, यह एक प्रोत्साहन है। चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और स्थिर क्षेत्रीय संबंधों की आवश्यकता, भारत के साथ बेहतर संबंधों को वांछनीय बनाती है। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं: सीमा विवाद, पाकिस्तान पर अविश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाएं बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी, वर्तमान वैश्विक परिवेश, जहां पुराने गठबंधन कमजोर दिखाई देते हैं और संरक्षणवादी भावनाएं प्रबल हैं, ने भारत और चीन के लिए व्यावहारिकता की नई खोज का मार्ग प्रशस्त किया है।

भारत पर आर्थिक दबाव डालकर, वाशिंगटन ने अनजाने में ही दिल्ली की विकल्पों की तलाश को तेज कर दिया है - जिससे बीजिंग एक आवश्यक, भले ही असहज, साझेदार बन गया है। तियानजिन बैठक में भले ही कोई नाटकीय सफलता न मिली हो, लेकिन इसने एक रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है। मोदी और शी जिनपिंग, दोनों ही अनुभवी नेता और मजबूत घरेलू जनादेश के साथ, आने वाले महीने इस बात की परीक्षा लेंगे कि क्या वे अपने इशारों को ठोस रूप दे पाते हैं। और उनके फैसलों पर ही एशिया का भविष्य टिका है।

लचीलापन दर्शाती भारत की आर्थिक संवृद्धि

बढ़ती आय के साथ बढ़ता कार्यबल न केवल उपभोग के लिए निकट अवधि का समर्थन प्रदान करता है, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में दीर्घकालिक विश्वास भी प्रदान करता है। उच्च विकास दर को बनाए रखना आगे के सुधारों, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने और उत्पादकता बढ़ाने पर निर्भर करेगा।

रोहित देव
लेखक, असम मुख्यमंत्री सचिवालय के मुख्य अर्थशास्त्री हैं।

अगस्त का महीना भारत से एक जबरदस्त संदेश लेकर आया है– जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल-पुथल के बीच एक अलग ही संदेश है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए हाल ही में जारी जीडीपी आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जिसका कई लोगों ने अनुमान लगाया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इतनी दृढ़ता से उम्मीद की थी: भारत की अर्थव्यवस्था लचीली, सुधार-उन्मुख और नए सिरे से विकास के लिए तैयार है। मोस्पी के आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल-जून 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है और पांच तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। यह प्रदर्शन भारत को न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाता है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी बनाता है जो अपने समकक्षों पर अपनी बढ़त लगातार बढ़ा रही है।

ये आंकड़े न केवल अपने पैमाने के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित स्थिति के बारे में जो संकेत देते हैं, उसके लिए भी उत्साहजनक हैं। आपूर्ति-पक्ष के चालकों, विनिर्माण, निर्माण और सेवाओं ने व्यापक गति को दर्शाते हुए मजबूत विस्तार दर्ज किया।

मांग पक्ष में, मजबूत निजी उपभोग और निवेश ने विकास का आधार प्रदान किया। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 60.3 प्रतिशत हो गई - जो 15 वर्षों में पहली तिमाही का उच्चतम स्तर है।

हाल के कई नीतिगत कदमों ने घरेलू धारणा को बढ़ावा दिया है: केंद्रीय बजट में आयकर राहत की घोषणा, रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती और खरीफ की बुवाई में अच्छी प्रगति, जिनमें से प्रत्येक ने प्रयोज्य आय में वृद्धि की है और वित्तीय स्थिति को आसान बनाया है। इस बीच, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो सार्वजनिक और निजी दोनों निवेशों में वृद्धि से समर्थित है। पहली तिमाही में सरकार का पूंजीगत व्यय पिछले तीन वर्षों की इसी तिमाही के औसत से 30.1 प्रतिशत अधिक था, जो बुनियादी ढांचे पर इसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

निजी क्षेत्र ने भी नया आत्मविश्वास दिखाया, नई निवेश घोषणाओं में साल-दर-साल 3.3 गुना वृद्धि हुई। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि क्षमता उपयोग क्रमिक और साल-दर-साल दोनों तरह से बढ़ा है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र आगे विस्तार के लिए तैयार दिखाई देता है।

इस वृद्धि के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता भी उतनी ही उत्साहजनक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में आठ साल के निचले स्तर पर आ गई, जिससे परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई और व्यवसायों को अधिक अनुमानित लागत संरचना मिली।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा-से-जीडीपी अनुपात 2025-26 में और कम होकर 4.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी से प्रेरित उच्च स्तर से स्थिर समेकन दर्शाता है। श्रम बाजार उत्साहजनक संकेत दे रहा है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन एक साल पहले की तुलना में 1.6 गुना अधिक था। शहरी बेरोजगारी महामारी-पूर्व स्तर से काफी नीचे बनी हुई है, जबकि भर्ती गतिविधि में तेजी बनी हुई है - नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक निरंतर भर्ती गति की ओर इशारा करता है।

> एक पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् ने तो यहां तक कहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति का संभवतः सबसे सटीक माप है। यदि मुद्रास्फीति कम है, तो स्वाभाविक रूप से डिफ्लेटर भी कम होगा। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ठीक यही स्थिति होगी।

बढ़ती आय के साथ बढ़ता कार्यबल न केवल उपभोग के लिए निकट अवधि का समर्थन प्रदान करता है, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में दीर्घकालिक विश्वास भी प्रदान करता है।

अपस्फीतिकारक के कम होने की चिंताएं भी निराधार हैं। मुद्रास्फीति संकेतक लागू करके नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्यों पर मूल्यांकित) को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर मूल्यांकित) में परिवर्तित करना एक दीर्घकालिक और विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रथा है। वास्तविक और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बीच एक छोटा सा अंतर केवल प्रचलित निम्न-मुद्रास्फीति परिवेश का एक सांख्यिकीय प्रतिबिंब है, न कि कोई आंकड़ा विसंगति।

जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर करता है, सीपीआई (घरेलू उपभोग तक सीमित) या डब्ल्यूपीआई (जिसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं) के विपरीत। एक पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् ने तो यहां तक कहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति का संभवतः सबसे सटीक माप है। यदि मुद्रास्फीति कम है, तो स्वाभाविक रूप से डिफ्लेटर भी कम होगा। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में ठीक यही स्थिति होगी।

आंकड़ों से परे, अगस्त एक प्रतीकात्मक उपलब्धि लेकर आया। एसएंडपी ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी' से बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया, जो 18 वर्षों में पहला उन्नयन था। यह मान्यता मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ी हुई मौद्रिक नीति विश्वसनीयता और राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता पर आधारित थी।

भारत के लिए, इस उन्नयन के वास्तविक आर्थिक परिणाम हैं। कम उधारी लागत, निवेशकों का बढ़ता विश्वास और विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है। बेशक, भारत वैश्विक प्रतिकूलताओं से अछूता नहीं है। नए अमेरिकी टैरिफ लगाने से निर्यातक बेचैन हैं, और बाहरी माहौल भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बदलते व्यापार समीकरणों से भरा हुआ है।

फिर भी, सरकार और उद्योग जगत इस मुश्किल घड़ी के लिए खुद को तैयार करते दिख रहे हैं, और उनके बीच लगातार बातचीत की खबरें आ रही हैं। आने वाली तिमाहियों में आधार प्रभाव कम होने के साथ विकास दर धीमी पड़ सकती है, लेकिन आधार रेखा अभी ऊंची है।

सुधारों के गहराने, निवेश में तेजी आने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बरकरार रहने के साथ, भारत वैश्विक औसत से कहीं बेहतर विकास दर बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए भारत का प्रदर्शन अभी अंतिम चरण नहीं है। सुधार का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन उच्च विकास दर को बनाए रखना आगे के सुधारों, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने और उत्पादकता बढ़ाने पर निर्भर करेगा।

इस सप्ताह जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है, इसलिए एक स्थिर, कम दर वाली संरचना के साथ जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि केंद्र की ओर से स्थिर वृहद आधार और सभी राज्यों की ओर से प्रतिस्पर्धी सुधारों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, तो भारत लचीलेपन को एक उच्च, अधिक स्थिर विकास पथ में बदल सकता है।

भारत में स्वास्थ्यरक्षा का भविष्य

> बढ़ती अपेक्षाओं, लोगों के तेजी से शहरी प्रवास और बढ़ती बीमारियों के बोझ के साथ, अस्पतालों को पारंपरिक उपचार से आगे बढ़कर उस समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहना चाहिए जिसकी वे सेवा करते हैं।

शरण शिवराज पाटिल
लेखक, आर्थोपेडिक सर्जन हैं।

छोटे भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बढ़ती अपेक्षाओं, लोगों के तेजी से शहरी प्रवास और बढ़ती बीमारियों के बोझ के साथ, अस्पतालों को पारंपरिक उपचार से आगे बढ़कर उस समुदाय के लिए प्रासंगिक बने रहना चाहिए जिसकी वे सेवा करते हैं। स्वास्थ्य सेवा समुदाय-केंद्रित, तकनीक-संचालित और भविष्य के लिए तैयार होनी चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा केवल उपचार पर आधारित नहीं है, यह जुड़ाव पर भी आधारित है। भारत में, शहरों का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, और समुदाय भी बहुत विविध, गतिशील और विकसित हो रहे हैं। इन जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने से हमें ऐसे देखभाल वितरण मॉडल तैयार करने में मदद मिलती है जो व्यक्तिगत और समावेशी लगें। उदाहरण के लिए, जब निवासी विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों से आते हैं, तो अस्पताल का वातावरण - कर्मचारियों की विविधता से लेकर भोजन मेनू जैसी साधारण बातों तक - सभी में उस समावेशिता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आजकल, एक आधुनिक अस्पताल को केवल एक उपचार केंद्र से कहीं अधिक होना चाहिए। यह एक सुपर-स्पेशलिटी पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए।

कार्डियोलॉजी, लिवर, किडनी और फेफड़ों के प्रत्यारोपण, रोबोटिक जोड़ प्रतिस्थापन, बाल रोग, प्रसूति और कैंसर विज्ञान जैसी कई उन्नत सेवाएं एक मजबूत निवारक और प्राथमिक देखभाल प्रणाली के साथ-साथ मौजूद होनी चाहिए। ये सभी एकीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि अस्पताल नियमित जरूरतों और अत्यधिक जटिल मामलों, दोनों को पूरा कर सकें, जिससे देखभाल की निरंतरता बनी रहे और मरीजों को उनके पूरे जीवन में लाभ मिले।

स्पर्श हॉस्पिटल्स में, यह दर्शन हमारी सभी आठ इकाइयों में पहले से ही लागू है, जिसमें हाल ही में शुरू की गई हेन्नूर रोड इकाई भी शामिल है, जिसने खुद को उन्नत, बहु-विशिष्ट देखभाल के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। आगामी सरजापुर इकाई

इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है, जो व्यापक विशेषज्ञताओं को एक ही छत के नीचे लाकर मरीजों को नियमित परामर्श से लेकर सबसे जटिल सर्जरी तक, निर्बाध देखभाल सुनिश्चित करती है। तकनीक नई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ और नींव है। इंटरऑपरेबल मरीज रिकॉर्ड वाले पेपरलेस अस्पताल सभी शाखाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करते हैं। कमांड सेंटर और रीयल-टाइम निगरानी के माध्यम से दक्षता में सुधार किया जा सकता है, जबकि एआई उपकरण और एप्लिकेशन - मरीजों के प्रवाह की भविष्यवाणी करने से लेकर नैदानिक निर्णयों का समर्थन करने तक - देखभाल को और अधिक सटीक बनाते हैं।

डिजिटल ऐप्स स्क्रीन पर टैप करके पंजीकरण, भुगतान, परामर्श और यहां तक कि आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से भी मरीजों को सशक्त बनाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक पारदर्शी, डेटा-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो सुरक्षा और विश्वास को प्राथमिकता देता है।

जैसे-जैसे शहर बढ़ते हैं, पहुंच स्वतः ही एक चुनौती बन जाती है। आवासीय और कॉर्पोरेट परिसरों में टेलीमेडिसिन आउटरीच केंद्र जनता तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। मरीज वर्चुअल माध्यमों से विशेषज्ञों से परामर्श भी ले सकते हैं, जबकि स्थानीय कर्मचारी निदान और नुस्खे का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे बार-बार अस्पताल जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। लोगों के रहने और काम करने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाकर, टेलीमेडिसिन उच्च-गुणवत्ता वाली विशेषज्ञता और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के बीच के अंतर को कम करता है। गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के कारण, समय पर पता लगाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और डेटा एनालिटिक्स द्वारा समर्थित रोकथाम और पूर्वानुमान ही आगे का रास्ता है। सरकार को भी बड़े पैमाने पर निवारक कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए पहल करनी चाहिए, जबकि निजी अस्पतालों को नियमित रूप से उन्नत निदान और उपचार उपलब्ध कराने चाहिए। भारत के तीन ऊर्ध्वाधर मॉडल इस दर्शन को दर्शाते हैं, जैसे कि पूर्वानुमानित और निवारक देखभाल; उन्नत हस्तक्षेपों और सर्जरी के साथ उपचारात्मक देखभाल; और पुनर्वास, स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से उपशामक उपचार, दीर्घकालिक सहायता, और जीवन के अंत में सम्मानजनक देखभाल।

भारत वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने की दहलीज पर खड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे वह आईटी में था। कुशल पेशेवरों, सुव्यवस्थित रोगी डेटा और नवीन देखभाल मॉडल की उपलब्धता बेजोड़ है।

गायब कड़ी अनुसंधान और नवाचार निवेश है। भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप किफायती, स्वदेशी समाधानों के नवाचार के माध्यम से, हम ऐसे मॉडल तैयार कर सकते हैं जो दुनिया का ध्यान आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य सेवा का भविष्य उन लोगों का है जो सामर्थ्य को नवाचार के साथ, समुदाय की प्रासंगिकता को वैश्विक मानकों के साथ, और रोकथाम को उपचार के साथ जोड़ते हैं—और भारत उस भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

आप की बात

खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे

खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे, यह कहावत आज अमेरिका पर बिल्कुल सही बैठती है। पहलगाम घटना के बाद से अमेरिका और भारत के कूटनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।अपरेशन सिन्दूर के स्थगन का श्रेय और भारत द्वारा रूस से तेल क्रय नहीं रोकने से क्षुब्ध राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोचा था कि भारत को यदि आर्थिक मोर्चे पर परेशान किया जाए तो वह विवश होकर अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। इसके लिए उसने भारत पर 50% की टैरिफ भी लगाकर देख लिया ,किन्तु उसका भी जब भारत पर प्रभाव होते नहीं दिखा तो ट्रम्प के सलाहकार पीटर नवारो अनर्गल प्रलाप पर उतर आए। ऊपर से चीन में चल रहे एस सी ओ सम्मेलन में जब भारत रूस और चीन तीन आर्थिक और सामरिक महाशक्तियों को एक साथ ठहाके मारते हुए अमेरिका ने देखा तो ट्रम्प के सीने पर सांप लोट गया। सम्मेलन के पहले दिन तो नवारो ने कहा कि रूस - यूक्रेन युद्ध मोदी युद्ध है। जबकि राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रम्प इसी युद्ध की जड़ तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन को बता रहे थे। सम्मेलन के दूसरे दिन नवारो ने एक बहुत ही घटिया बयान दे डाला कि रूसी तेल खरीद से भारत के ब्राह्मण मालामाल हो रहे हैं। जबकि तेल खरीद और बिक्री से भारत के किसी ब्राह्मण का कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि भारत के शीर्ष पांच उद्योगपतियों में से एक भी ब्राह्मण नहीं है।

– डॉ नरेंद्र टोंक, मेरठ

पीएम मोदी का डिजिटल विजन

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल विजन का अहम हिस्सा है। डिजिटल इंडिया, आधार, यूपीआई और सशक्त दूरसंचार नेटवर्क ने हर भारतीय को तकनीक से जोड़ा और इसी बुनियाद पर देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया। अब यही इकोसिस्टम भारत को चिप निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है।आज भारत में 65 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का स्तर सालाना 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी नई तकनीकों में चिप्स की भारी मांग है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। दशकों तक यह धारणा रही कि भारत इस दौड़ में पीछे रह गया है, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार ने दस बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। गुजरात के साणंद में पायलट प्रोडक्शन लाइन पहले ही शुरू हो चुकी है और इस साल पहला 'मेड इन इंडिया' चिप बाजार में उपलब्ध होगा। अगले एक वर्ष में चार और यूनिट्स के उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा।

– मधु सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

लोगों को जागरूक होना होगा

परदेश जाके परदेसिया, ना लाना एड्स अपनी दुअरिया'। एक ऑटो के पीछे लगे इस पोस्टर को देखा। इस नारे का मर्म समझना जरूरी है। भारत विकासशील देश है, विकास के मामले में क्षेत्रीय असमानता की वजह से रोजगार की तलाश में लोग अपने घर से दूर विकसित राज्यों व शहरों में चले जाते हैं। परिवार से दूरी के चलते यौन इच्छा प्रबल रहती है। ऐसे में यौन इच्छा की प्रबलता गलत राह पर ले जाती है। ऊपर बताये गये नारे के सहारे भारतीय महिलाएं सुदूर प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने वाले अपने पतियों को बीमारी से बचने का संदेश देती हैं। बेशक, एड्स फैलने के कई कारण हैं, लेकिन असुरक्षित यौन संबंध एक बड़ा कारण है। आज भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारे लोगों को एड्स के बारे में सही जानकारी नहीं है। जिसे जानकारी है भी, तो वे बताने से कतराते हैं कि कहीं इसकी भनक लोगों को लगा तो समाज में उन्हें कलंकित समझा जायेगा। इस कारण आज एड्स पीड़ित व्यक्ति बिना बीमारी बताये अपने साथ-साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। तेजी से फैलती इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए देश की सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाएं सार्थक पहल कर रही हैं। अब जरूरत है लोगों को जागरूक होने की।

– संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

शिक्षक बनने की जटिल प्रक्रिया

शिक्षक बनने की प्रक्रिया आज परीक्षाओं के मकड़जाल में फंस गई है। बीएड, बीटीसी, टीईटी, सुपर टीईटी जैसी कई परीक्षाओं की श्रृंखला ने शिक्षक अभ्यर्थियों को उलझा दिया है। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए टीईटी अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा छोड़नी पड़ेगी या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेनी होगी। यह स्थिति एक गंभीर सवाल खड़ा करती है—क्या वास्तव में इन अलग-अलग परीक्षाओं से शिक्षक की गुणवत्ता तय होती है? सच तो यह है कि बीएड और बीटीसी जैसे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर पढ़ाई हो, व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाए और नियमित मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी हो, तो अलग से टीईटी या सुपर टीईटी जैसी परीक्षाओं की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरी ओर, इन परीक्षाओं के नाम पर मोटी फीस लेकर बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को वर्षों तक तैयारी और परीक्षा की दौड़ में उलझाए रखना शिक्षा सुधार का उपाय नहीं बल्कि उनकी आर्थिक और मानसिक थकान का कारण बन गया है। आवश्यकता इस बात की है कि भर्ती प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। शिक्षक जिस तरह पढ़ाते हैं और छात्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर निगरानी और मूल्यांकन ज्यादा कारगर साबित हो सकता है।

– आर के जैन, बड़वानी, मप्र

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 169

वस्तु एवं सेवा कर में सुधार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज आरंभ हो रही दो दिवसीय बैठक से पहले गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दलों द्वारा शासित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने गत सप्ताह एक बैठक की ताकि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में संभावित बदलावों का आकलन कर सकें। उनके सुझाव यह संकेत देते हैं कि वांछित बदलावों का क्रियान्वयन करना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए समूह ने नुकसानदेह और विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी की दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि अतिरिक्त शुल्क से प्राप्त राशि पूरी तरह राज्यों को स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा संबंधित राज्यों ने कहा है कि 2024-25 के आधार वर्ष होने के कारण अगर वृद्धि 14 फीसदी से कम रहती है तो उनके राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। जीएसटी दरों के प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण करीब 85,000 करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा था कि जीएसटी व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाएगा। बाद में पता चला कि व्यवस्था को सैद्धांतिक तौर पर 5 फीसदी और 18 फीसदी की दो दरों वाले ढांचे पर लाया जाएगा और अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को इन दो दरों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानदेह वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की दर रहेगी। इस बात पर जोर देना उचित होगा कि विशेषज्ञ लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि दरों की विविधता ने जीएसटी प्रणाली के कामकाज और प्रदर्शन को प्रभावित किया है। ऐसे में उन्हें युक्तिसंगत बनाने की कवायद काफी समय से लंबित थी। बहरहाल, कुछ राज्यों की चिंताएं और उनके द्वारा सुझाए गए हल बताते हैं कि दरों और स्लैब को सुसंगत बनाने की दिशा में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा।

उदाहरण के लिए राज्यों को संभावित राजस्व हानि की भरपाई करने का विचार अत्यंत कमजोर है। उन्हें जीएसटी के शुरुआती पांच साल तक क्षतिपूर्ति उपकर के जरिये भरपाई की गई है। जब उपकर संग्रह महामारी के दौरान कम हो गया तो उन्हें उधारी के जरिये भरपाई की गई। फिर उसे चुकाने के लिए उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई गई। यह व्यवस्था हमेशा जारी नहीं रह सकती। इसलिए, जब परिषद दरों में बदलाव पर विचार कर रही है, तो कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को केवल घरेलू मांग को बढ़ाने के उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ लोगों का तर्क है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण संभावित निर्यात हानि की भरपाई के लिए करों को कम किया जाए। बल्कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना और राजस्व संग्रह को बेहतर करना होना चाहिए। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन तथा अन्य लोगों ने इसी समाचार पत्र में लिखा, वास्तविक लागू जीएसटी दरें व्यापक दर स्लैब से ऊंची हैं। समस्या का एक हिस्सा उपकर संग्रह के अंत के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगर उपकर को जीएसटी दर में समाहित कर लिया जाना है तो इसे सावधानी से पूरा करना होगा।

राजस्व संग्रह के मामले में सरकार ने दिसंबर 2024 में संसद को सूचित किया कि 2023-24 में औसत जीएसटी दर 11.64 फीसदी थी, जो कि सरकारी समिति द्वारा सुझाई गई 15-15.5 फीसदी की राजस्व निरपेक्ष दर से काफी कम थी। जीएसटी लागू होने के समय इसकी औसत दर 14.4 फीसदी थी। दरों में जल्दबाजी में की गई कटौती ने राजस्व संग्रह को प्रभावित किया। परिषद को वही गलती दोहराने से बचना चाहिए। राज्यों का यह तर्क उचित है कि वे जीएसटी पर अधिक निर्भर हैं। इसलिए उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे राजस्व बढ़ाने के उपाय खोजें, न कि किसी मुआवजे पर निर्भर रहें। केंद्र और राज्य दोनों को राजस्व संग्रह में सुधार करना होगा ताकि सरकार का कुल घाटा और ऋण एक टिकाऊ मार्ग पर बना रह सके।

बिनय सिन्हा

जीएसटी में दो चरणों वाले सुधार की दरकार

कर दरों को तर्कसंगत बनाना एक लंबा लक्ष्य हो सकता है, हालांकि केंद्रीय जीएसटी में एकतरफा कटौती से कम समय में घरेलू मांग को बढ़ावा मिल सकता है। बता रही हैं आर कविता राव

भारत के कारोबारी जगत के मौजूदा आर्थिक माहौल के बीच ही इसे एक और झटका लगा है। अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित दंडात्मक शुल्क 27 अगस्त से लागू हो गए हैं। इसके तहत भारत के विभिन्न तरह के निर्यात पर 50 फीसदी का आयात शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों का प्रभाव वस्त्र, जूते-चप्पल, रत्न एवं आभूषण और झींगा निर्यात सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा, दूसरे चरण के प्रभाव दिखने की भी आशंका जताई जा रही है जैसे कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात में कमी। रत्न एवं आभूषण एक ऐसा ही क्षेत्र हैं जिसमें निर्यात वास्तव में कच्चे हीरों के आयात से जुड़ा हुआ है।

हालांकि, राजनयिक तरीके से कम शुल्कों वाले दौर में वापस लौटने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं लेकिन भारत सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट रूप से नई पहलों को शामिल करेगी जिसमें नए बाजारों की तलाश करना और अल्पावधि में निर्यात करने वाली इकाइयों की मदद करने वाली नीतियां बनाना भी शामिल है। निर्यात क्षेत्र को लक्षित करने वाले नीतिगत पहलों के अलावा, निर्यात मांग की जगह घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक उपाय भी किए जाने की संभावना है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में सुधार करते हुए इसे युक्तिसंगत बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह बदलाव अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। फिलहाल, जीएसटी की व्यवस्था में सुधार के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, लंबे समय की प्रतिबद्धता के अनुसार, दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना, जीएसटी की दरों को व्यवस्थित करना और कर स्लैब की संख्या कम करना है। दरों को तार्किक बनाए जाने की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है और इसका लक्ष्य, एक ऐसी कर व्यवस्था स्थापित करना है जो लंबे समय तक टिकाऊ हो। दूसरा, अल्पकालिक स्तर पर अर्थव्यवस्था के मौजूदा आर्थिक झटके और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को देखते हुए, घरेलू मांग को बढ़ावा देना आवश्यक लक्ष्य हो सकता है। इस मांग में दो चीजें शामिल हैं, परिवारों में खपत और सरकार द्वारा किया गया खर्च, खासतौर पर पूंजीगत व्यय। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था तैयार करनी होगी। सुधारों की रूपरेखा तय करते समय कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है:

1. मांग बढ़ाने के लिए, कर की दरें कम करने की सलाह दी जाती है। मांग पर सकारात्मक असर तभी होगा जब कर में कमी का लाभ, कीमतों में कमी के रूप में ग्राहकों तक पहुंचे। जीएसटी लागू होने के समय, मुनाफाखोरी रोकने के प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कीमतों में तुरंत कमी आए। लेकिन, ऐसे प्रावधान विवादास्पद होते हैं इसलिए बाजार की शक्तियों पर निर्भर रहना बेहतर है। हालांकि, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिसका मतलब है कि मांग में वृद्धि धीरे-धीरे होगी।

2. कर दरों में कमी का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत में बदलाव के प्रति कितनी संवेदनशील है। जब मांग बहुत ज्यादा लचीली होती है तब कर दर कम करने से उसकी मांग अधिक होती है, जिससे कुल राजस्व बढ़ सकता है। लेकिन, अगर मांग कम है, तब कर कम करने से राजस्व में कमी आ सकती है। इससे, जीएसटी राजस्व पर इसका कुल प्रभाव अनिश्चित रहता है।

3. जीएसटी, राज्य सरकारों के राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रतिबद्धताओं और कर्ज लेने की सीमाओं को देखते हुए अगर जीएसटी दरों में कमी से राज्यों के राजस्व पर तुरंत कोई बुरा असर पड़ता है, तो इससे उनके पूंजीगत व्यय में कमी आ सकती है। राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वित्त आयोग अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे रहा है, जो मौजूदा कर व्यवस्था पर आधारित हैं। दरों में बदलाव से केंद्रीय राजस्व पर भी असर पड़ेगा, जिसका बाद में राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है।

4. एक संघीय अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को वृहद स्तर पर स्थिर रखने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता के समय में कर्ज लेने की क्षमता केंद्र के पास अधिक होती है। ऐसे में अल्पकालिक अनिश्चितताओं का बोझ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, एक संभावित तरीका यह है कि जीएसटी सुधार दो चरण में किए जाएं। पहला, दीर्घकालिक सुधार से जुड़ा है जिसका लक्ष्य, कर दरों की संख्या कम करना है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुल राजस्व पर ज्यादा असर न पड़े, यानी पहले जितना राजस्व मिलता था, उतना ही मिलता रहे। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ वस्तुओं पर कर दर बढ़े और कुछ पर घटे।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है। अगर हम राजस्व को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह एक उपयोगी बेंचमार्क होगा। हमें इसका अनुपात स्थिर रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस तरह का तालमेल बिठाने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर की दर बढ़ानी होगी जबकि कुछ पर घटानी होगी। उदाहरण के लिए, कई वस्तुएं जो अभी कर के दायरे से बाहर हैं, उन्हें कम दर के साथ कर दायरे में लाया जा सकता है। जिन वस्तुओं पर अभी 12 फीसदी कर लगता है, उन्हें ऊंची कर स्लैब में रखा जा सकता है। सही से तैयार की गई दो या तीन दरों वाली कर व्यवस्था मध्यम अवधि में स्थिर रह सकती है और निवेशकों के लिए भी नीतिगत स्थिरता प्रदान कर सकती है।

वर्तमान सुधार एजेंडा का दूसरा भाग यह हो सकता है कि केंद्र सरकार एकतरफा और कम समय के लिए कर की दरें कम करे। यह राज्यों की जीएसटी को बिना बदले, सिर्फ केंद्रीय जीएसटी को कम करके किया जा सकता है। यह कदम कुछ वैसा ही होगा जैसा कि वैश्विक वित्तीय संकट के असर को कम करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी।

जब व्यवस्था स्थिर हो जाए, तब यह दी गई छूट वापस ली जा सकती है। अगर कर में यह बदलाव केंद्र सरकार करती है, तो राज्यों के वित्त पर इसका असर कम पड़ेगा। यह भी साफ है कि सरकारी खर्चों से बढ़ने वाली मांग को कर प्रोत्साहन उपायों से कमजोर होने से बचाने के लिए वित्तीय नियमों में कुछ ढील देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो थोड़े समय के लिए राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह की दो स्तर वाली सुधार प्रक्रिया, राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मददगार साबित हो सकती है और नीतिगत स्थिरता भी दे सकती है, इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है।

(लेखिका राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली की निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

प्रवासन समस्या नहीं शहरी विकास का आधार

दशकों से भारतीय शहर अवसरों के प्रमुख केंद्र रहे हैं, जो सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से उम्मीद जगाते हैं। लाखों प्रवासी, ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में चले गए हैं। मुंबई की कपड़ा मिलों से लेकर बेंगलूरु के प्रौद्योगिकी केंद्रों तक दरअसल ये प्रवासी एक ऐसी छिपी हुई ताकत हैं जो भारत के शहरी क्षेत्रों में बदलाव को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। यह गतिशीलता वास्तव में, भारत की विकास की कहानी में कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि इसकी केंद्रीय भूमिका रही है।

हालांकि इन दिनों भय आधारित शासन का एक उभरता रुझान, अब इस प्रणाली को खतरे में डाल रहा है। इसके कारण ही ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या भारत के शहर, प्रवासन के इंजन के रूप में काम करते रह सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप, ये आर्थिक वृद्धि और विकास के इंजन के रूप में भी काम करना जारी रख सकते हैं।

भारत में आंतरिक पलायन बड़े पैमाने पर होता रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 45 करोड़ से अधिक आंतरिक प्रवासी थे जो आबादी का लगभग 37 फीसदी है। विश्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार, यह एक दशक पहले दर्ज किए गए 30 फीसदी से काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन एक प्रमुख घटक रहा है क्योंकि कुछ राज्यों ने वर्ष 2001-2011 के दौरान अपनी शहरी आबादी में लगभग 30 फीसदी की वृद्धि देखी है और यह मुख्य रूप से पलायन के कारण ही संभव हुआ। आबादी में दिख रहे बदलाव के कारण, देश के आर्थिक भूगोल को एक नया रूप मिला है। वास्तव में प्रवासी न केवल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण हैं बल्कि इनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 45 फीसदी तक का योगदान है। साथ ही ये प्रवासी संगठित क्षेत्रों के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं जो कम लागत वाले संसाधन के रूप में उनके श्रम पर निर्भर होते हैं।

शहरीकरण का प्रबंधन जब सूझ-बूझ से किया जाता है तब इसके कारण गरीबी के स्तर में लगातार कमी आती है और इसका संबंध जीवन स्तर में सुधार के साथ भी जुड़ा है। विकासशील अर्थव्यवस्था में, शहरों में प्रवासन से गरीब परिवारों की आय बढ़ती है और इस वर्ग की सेवाओं तक पहुंच भी होती है। यह रुझान विशेष रूप से भारत जैसे देशों में दिखता है जहां शहरी क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर और मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के तौर पर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 से पता चलता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में औसत वार्षिक मजदूरी (88,604 रुपये), ग्रामीण क्षेत्रों (45,785 रुपये) की तुलना में लगभग दोगुनी है।

अमित कपूर

किसी भी कानूनी प्रतिबंध की तरह, भय का माहौल बनना भी प्रवासन के लिए एक प्रभावी गतिरोध हो सकता है। भारत में आंतरिक स्तर पर पासपोर्ट का चलन नहीं है फिर भी कुछ बाधाएं अक्सर अदृश्य रूप से मौजूद होती हैं। इसमें भाषा सहित कुछ अन्य बुनियादी अंतर, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक अंतर्निहित धारणा यह भी है कि एक नए राज्य या शहर में प्रवेश करने का अर्थ वास्तव में एक नए सामाजिक और प्रशासनिक वातावरण को समझना और उसके हिसाब से सामंजस्य बिठाना है। प्रवासियों के लिए, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, स्वास्थ्य सेवा, आवास और बुनियादी राशन तक पहुंच अक्सर इसी कमजोर आत्मीयता की भावना पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों में, यह भावना कमजोर हो गई है।

विशिष्ट भाषाई, जातीय या धार्मिक समूहों को लक्षित करने वाले राजनीतिक बयानों और प्रशासनिक उपायों ने प्रवासी आबादी के बीच असहजता पैदा कर दी है। विशेष रूप से, 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अचानक नौकरी छूटने, घर को लेकर बनी असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, परिवहन का साधन न होने के बावजूद लाखों प्रवासी पैदल या किसी से मदद लेकर अपने गांवों में वापस चले गए और कई लोग वापस नहीं लौटे। यह विभाजन के बाद भारत में शायद सबसे बड़ा सामूहिक पलायन था, जिससे पता चला कि बिना सुरक्षा गारंटी के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए शहरी जीवन कितना कमजोर और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यह चुनौती और कमजोरी तब और बढ़ जाती है जब शासन ही भय का स्रोत बन जाता है। नीतियां भी बाहरी लोगों के बारे में मतभेद करती हुई प्रतीत होती हैं, चाहे वह पुलिस जांच, दस्तावेज सत्यापन अभियान, या मनमाने तरीके से लागू किए जाने वाले कानून या नियम हों। इनके कारण ऐसा माहौल बनता है जिससे प्रवासी यह आकलन करने लगते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति वास्तव में अपने मूल स्थान पर वापस लौट जाने में है। वहीं शहरों को दो तरह से नुकसान होता है। सबसे पहले, प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर क्षेत्रों में तत्काल बाधाएं खड़ी होती हैं यानी निर्माण परियोजनाएं रुक जाती हैं, सेवा उद्योग को भर्ती करने में कठिनाई होती है और लागत बढ़ जाती है। दूसरा, शहरी शासन में दीर्घकालिक स्तर पर भरोसा कम होने से उन श्रमिकों को आकर्षित करना और बनाए रखना कठिन हो जाता है जो आर्थिक गतिशीलता की धुरी होते हैं।

सांस्कृतिक लागतों को मापना कठिन होता है लेकिन वे कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। प्रवासी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के भी वाहक होते हैं जो शहरों को महानगरीय शक्ल देते हैं। वे अपने साथ नए व्यंजन, भाषाएं और उद्यमशीलता के लिए काफी ऊर्जा का स्रोत लाते हैं। इस गतिशील तंत्र के अभाव में, शहरों के अधिक संकीर्ण होने, कम नवाचारी और आखिरकार वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बनने का जोखिम होता है। किसी शहर में प्रवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य स्थान के रूप में विश्वास बहाल करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक लाभों को सहजता से दूसरों तक पहुंचाना महत्त्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं जो प्रवासियों को स्थान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों तक पहुंच बनाने की गुंजाइश देते हैं, वास्तव में वे उन सारी असुरक्षा को कम करते हैं जो उन्हें शहरों से बाहर जाने को मजबूर कर सकती है। राज्य की सीमाओं को पार करते समय अफसरशाही के स्तर पर गतिरोध दूर करना, नियमों को सुसंगत बनाना और यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि बुनियादी सेवाएं किसी निश्चित, दीर्घकालिक आवास या निवास पर ही निर्भर न हों। भारत का शहरी बुनियादी ढांचा पहले से ही भारी दबाव का सामना कर रहा है। ऐसा अनुमान है कि देश को अपनी शहरी मांग पूरी करने के लिए अगले 15 वर्षों में 840 अरब डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी। ये निवेश तभी सफल होंगे जब शहर की अर्थव्यवस्था चलाने वाली मानव पूंजी को बरकरार रखा जाए। शहर अपने आप में बेहद जटिल है और इनकी सेहत खुलेपन, वस्तुओं, विचारों और लोगों की आवाजाही पर निर्भर करती है। भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, उसके लिए सबक स्पष्ट है कि प्रवासन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे दूर करना है, बल्कि यह वास्तव में शहरी जीवन शक्ति का स्रोत है।

भय से अल्पकालिक राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यह समृद्धि की नींव को कमजोर कर देता है। ऐसे में विकास का इंजन बने रहने के लिए, भारतीय शहरों को विश्वास का इंजन भी बनना होगा।

(लेखक इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस के चेयरपर्सन हैं। इस आलेख में मीनाक्षी अजित का भी सहयोग है)

आपका पक्ष

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देशवासियों से त्योहारों में स्वदेशी अपनाने की बात की। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में हमें स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना चाहिए, ताकि हमारे देश के घरेलू और कुटीर उद्योगों को आर्थिक फायदा हो। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें ज्यादातर वह सामान खरीदना चाहिए जो देश में ही तैयार होता है। अर्थात हमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रति रुचि बढ़ाने की जरूरत है। हमें वोकल फॉर लोकल की राह चलने की जरूरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने यह भी तर्क दिया है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह सब जरूरी है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो यह पता चलेगा कि स्वदेशी ही हमारे देश की स्वाधीनता संग्राम का मूलमंत्र रहा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाकर देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। लेकिन मौजूदा दौर वैश्विक बाजार का है। इस दौर में हम बिल्कुल यह नहीं कह सकते कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरी तरह स्वदेशी आंदोलन चला पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के पास अभी भी बहुत-से ऐसे कच्चे माल की व्यवस्था नहीं है जो देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि विदेशी कंपनियों के कारण जिन लोगों को देश में रोजगार मिला है, अगर स्वदेशी कारण इन कंपनियों को नुकसान होगा तो क्या यह अपने कर्मचारियों की छंटनी करेंगी और क्या इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों से त्योहारों में स्वदेशी अपनाने की बात कही

सट्टे और जुए के ऑनलाइन ऐप पर रोक उचित

तेजी से पैसा कमाने के तौर पर शुरू हुई ये आदत युवाओं में व्यसन का रूप ले रही है। यह आर्थिक हानि के साथ मानसिक तनाव और अंधकारमय भविष्य भी दे रहा है। युवा इसके कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं। देश के करोड़ों युवक इसके शिकार हैं। सरकार को नए कानून को प्रभावी बनाना चाहिए जिससे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर पूर्णतः रोक लग सके।

विमलेश पगारिया, बदनावर

ऑनलाइन गेम पर रोक सही

रियल मनी गेमिंग की लत ने देश की एक तिहाई आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लोग जीवन भर की जमा पूंजी गंवा कर कंगाल हो रहे थे। ऐसे में इस पर लगी रोक बहुत हितकारी और दूरगामी परिणाम देने वाली साबित होगी। ऐसी सट्टेबाजी से सरकार का राजस्व बढ़ सकता था मगर सरकार ने इस पर रोक लगा दी।

ईश्वर चंद गर्ग, कैथल

3.8 अरब डॉलर का कारोबार

देश के करीब 45 करोड़ वयस्क एवं वयस्क रियल गेमिंग की गिरफ्त में थे और अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 20 हजार करोड़ रुपये गंवा चुके हैं। कई लोगों ने इस बुरी लत के कारण आत्महत्या भी कर ली। सरकार ने इस पर रोक लगाकर बेहतर काम किया है। इससे ऑनलाइन गेमिंग के 3.8 अरब डॉलर के कारोबार को झटका लगा है। इस कानून का कड़ाई से पालन कराना जरूरी है।

अनिल कोथुलकर, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने तथा बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार शाम 4 बजे 206.03 मीटर दर्ज किया गया। राजधानी के निचले इलाकों में नदी का पानी भर जाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया गया है।